कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

रैलियां

विजय शंखनाद महारैली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)........ 6
हुंकार रैली, मुजफ्फरपुर (बिहार)........ 8
गुलबर्ग रैली (कर्नाटक)........ 9
जगरांव रैली (पंजाब)........ 11
पूर्वोत्तर (ईटानगर/गुवाहाटी/अगरतला) रैली........ 12

लेख

आचरण संबंधी एकाकीपन
– **अरुण जेटली**........ 14
सबसे बड़ा चुनावी उत्सव
– **हृदयनारायण दीक्षित**........ 15
भाजपा, कांग्रेस और दलित प्रश्न
– **डॉ. उदित राज**........ 17
भाजपा के प्रति बढ़ती अनुकूलता
– **राजनाथ सिंह सूर्य**........ 19
आर्थिक समृद्धि का रास्ता है मोदीनामिक्स
– **कंचन गुप्ता**........ 21
वक्त की नब्ज : नए भारत की नींव
– **तवलीन सिंह**........ 23
कांटों भरी राजनीति
– **स्वप्न दासगुप्ता**........ 25

अन्य

'नरेन्द्र मोदी– ए विक्टिम ऑफ मैनीपुलेशन्स'' का लोकार्पण........ 28

मुख पृष्ठ : 2 मार्च 2014 को विजय शंखनाद महारैली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

सत्रहवीं शताब्दी के महान संत कवि
संत तुकाराम
की जयंती (18 मार्च) पर उन्हें शत्-शत् नमन!

बोध कथा

शंकर की मां

आदि शंकराचार्य के बचपन का नाम था- शंकर। आठ साल की उम्र में ही उन्होंने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ने का निश्चय किया। यह उनकी माता विशिष्टा देवी के लिए एक आघात था। उन्होंने जब अपने बेटे को रोकना चाहा तो शंकर ने उन्हें नारद से संबंधित कथा सुनाई। कथा के मुताबिक नारद जब मात्र पांच वर्ष के थे, तभी वे अपने स्वामी की अतिथिशाला में अतिथियों के मुंह से हरिकथा सुनकर साक्षात हरि से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। मगर अपनी मां के स्नेह के कारण गृह त्याग का साहस न जुटा पाए। एक रात सर्पदंश से मां की मृत्यु हो गई। इसे ईश्वर की कृपा मानकर नारद ने गृह त्याग कर दिया।

यह कथा सुनाकर बालक शंकर ने अपनी मां से कहा- मां, जब नारद ने घर का त्याग किया, तब वे मात्र पांच वर्ष के थे। उन्हें मातृ वियोग सहन करना पड़ा था। मैं तो आठ वर्ष का हूं और मेरे ऊपर तो मातृछाया सदैव रहेगी चाहे मैं कहीं भी क्यों न रहूं। मां के प्रति शंकराचार्य की अटूट भक्ति थी। जब उन्होंने मां को छोड़ा तो बार-बार कहा- मैं कोई पत्थर हृदय नहीं हूं जो मां को रोता-बिलखता छोड़कर जा रहा हूं। बाद में शंकर ने लोगों को बताया- मेरी मां ने जब संतान मांगी थी, तो उन्हें बता दिया गया था कि पुत्र यदि अल्पज्ञ होगा तो दीर्घजीवी होगा और सर्वज्ञ होगा तो अल्पजीवी होगा। मां ने तब सर्वज्ञ मांगा था। चूंकि अल्पायु में ही मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए वृहत्तर कल्याण के लिए मैंने अपनी मातृभक्ति का बलिदान दिया। शंकराचार्य ने जो संकल्प किया था, वह करके दिखाया।

संकलनः अंजु अग्निहोत्री

(नवभारत टाइम्स)

व्यंग्य चित्र

साभार : जनसत्ता

साभार : रा. पत्रिका

सम्पादकीय

बज गई चुनावी रणभेरी

लोकसभा चुनाव-2014 का बिगुल बज चुका है। पहली बार नौ चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव 7 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को संपन्न होंगे। मतों की गिनती 16 मई को होगी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा के चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव में पहली बार 'नोटा' का विकल्प होगा। इसी दौरान आठ राज्यों की लगभग दो दर्जन विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होंगे। इस बार करीब 81.4 करोड़ मतदाता मत डालेंगे। और 10 करोड़ नए मतदाता हैं।

चुनाव को लोकतंत्र का पर्व कहा गया है और यह तो आम चुनाव है यानी लोकतंत्र का महापर्व। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां लोकतंत्र की जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं। चुनावी हिंसा लगभग खत्म हो गई है। भारतीय मतदाताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खारिज करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूर्व में माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के फरमान के बावजूद भारी संख्या में मतदाताओं ने बेखौफ होकर मतदान किया है। लेकिन चुनाव में केवल मतदान करना ही लोकतंत्र नहीं है। सोच-समझकर मतदान देने से ही लोकतंत्र और सशक्त होगा। बिना किसी लालच और स्वार्थ के, जाति-पंथ के पूर्वग्रहों से मुक्त होकर एवं धनबल व बाहुबल को शिकस्त देते हुए योग्य एवं साफ छवि के प्रत्याशी को चुनने से लोकतंत्र जीवंत होगा।

भारतीय जनता पार्टी ने छह महीने पहले ही श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। देश भर में विजय संकल्प रैली आयोजित हो रही है। श्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह इन रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इनमें जनज्वार उमड़ रहा है। बच्चे, युवा, महिलाएं, वृद्ध- हर उम्र के लोग बढ़-चढ़कर रैलियों में भाग ले रहे हैं। हर रैली ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। यह इस बात का संकेत है कि देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। वहीं, कांग्रेस का बुरा हाल है। वह प्रधानमंत्री पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करने की हिम्मत नहीं दिखा सकी जबकि तीसरा मोर्चा को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है।

पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। भाजपा व श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे भी भाजपा के लिए खुशखबरी बता रहे हैं। लेकिन इन सब अनुकूलताओं के बावजूद भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जी-जान से जुटना होगा। इस बात की चर्चा है कि इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया की प्रभावी भूमिका होगी लेकिन हमें सोशल मीडिया पर अपनी दमदार उपस्थिति के साथ-साथ जमीनी चुनाव अभियान पर विशेष ध्यान देना होगा। हर गांव व हर घर में दस्तक देना होगा। लोगों से संपर्क कर पार्टी के पक्ष में मेहनत करनी होगी। बूथ स्तर पर समिति बनाकर पार्टी की स्थिति और मजबूत करनी होगी।

कांग्रेसनीत यूपीए के 10 साल के शासनकाल में देश को आजादी के बाद के सबसे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। बेलगाम महंगाई, चरम भ्रष्टाचार और बेतहाशा बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ऐसे में प्रमुखी विपक्षी दल के नाते भाजपा का यह दायित्व बनता है कि वह जनता को तकलीफों से मुक्ति दिलाएं। जनता भाजपा की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। जनता में भारी उत्साह है और वह कांग्रेसनीत यूपीए के कुशासन का अंत कर जनता देश भर में कमल खिलाने को आतुर है।

इस बार का चुनाव निर्णायक और ऐतिहासिक है। भारत को विकसित और परमवैभव पर पहुंचाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर होना समय की मांग है। ■

विजय शंखनाद महारैली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

भाजपा की आंधी में स-ब-का विनाश तय : नरेंद्र मोदी

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने सपा, बसपा और कांग्रेस की 'धर्मनिरपेक्षता' पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये दल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति साधते हैं जबकि भाजपा के लिये इसका मतलब लोगों को जोड़ना और विकास करना है।

गत 2 मार्च को लखनऊ में आयोजित 'विजय शंखनाद महारैली' में श्री मोदी ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस अपनी विफलताएं छुपाने के लिये धर्मनिरपेक्षता का नकाब पहनकर देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनसे जब रोजगार, शिक्षा की व्यवस्था करने और महंगाई कम करने की बात की जाती है तो वे इन मुद्दों को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता को खतरे में होने की बातें करने लगते हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारे लिये धर्मनिरपेक्षता का मतलब है 'इंडिया फर्स्ट'। उनका 'सेक्युलरिज्म' केवल चुनावी नारा है, हमारा 'सेक्युलरिज्म' पंथनिरपेक्षता है। उनकी धर्मनिरपेक्षता केवल लोगों को डराना है लेकिन हमारा 'सेक्युलरिज्म। आर्टिकल ऑफ फेथ' है, लोगों को जोड़ना और विकास करना है। जो लोग हमें ललकारते हैं, उन्हें मेरी ललकार है.. ''आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की।''

उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए श्री मोदी ने कहा, ''हजयात्रा करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। गुजरात में हर वर्ष सिर्फ 4800 लोगों को कोटा दिया है लेकिन जब अर्जी मंगवाते हैं तो गुजरात में 38 हजार अर्जियां आती हैं और सेक्युलरिज्म की रेवड़ियां बांटने वाले लोगों के राज में 32 हजार के कोटे में अर्जियां सिर्फ आती हैं 35 हजार।'' उन्होंने कहा ''अगर यहां मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो इतनी कम अर्जियां नहीं आतीं। नेताजी आपने मुसलमानों को वोट का टुकड़ा ही समझकर रखा है।''

श्री मोदी ने कहा, ''अभी चुनाव की गर्मी शुरु होना बाकी है। उसके बावजूद यह जनसमर्थन देखकर साफ लग रहा है कि भाजपा की आंधी चल रही है। चुनाव घोषित होते ही यह सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा और सबका विनाश तय है। 'स' का मतलब सपा, 'ब' का मतलब बसपा और 'का' का मतलब कांग्रेस। इस 'सबका' ने सबको लूटा है, इसलिये उनका विनाश तय है।''

उन्होंने सपा प्रमुख पर हमला करते हुए कहा कि नेताजी ने अपने भाषण में पराजय स्वीकार कर ली। वह अपने भाषण में कह रहे थे कि श्री मोदी जी रैलियों में भीड़ एकत्र करने में मुकाबला मत करो। मतलब इसमें तो उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली।

श्री मोदी ने कहा, ''नेताजी कहते हैं कि श्री मोदी विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। मैं विकास की राजनीति का पक्षधर रहा हूं। मैं 10 साल से कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति छोड़ो, विकास के मुद्दे पर आओ। मुझे खुशी

है कि नेताजी को अपने पुराने रास्ते छोड़कर अपने भाषण में विकास की चर्चा करने को मजबूर होना पड़ा। यह उनकी दूसरी पराजय है।'' उन्होंने कहा कि श्री अखिलेश यादव गुजरात की आलोचना कर रहे हैं। अच्छा होता अगर वह उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार के काम का हिसाब देते। इस सरकार के कार्यकाल में एक साल में 150 दंगे कराए गये। गुजरात में 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। कहीं कर्फ्यू तक नहीं लगा।

श्री मोदी ने कहा, ''नेताजी शर्म से माथा झुक जाता है। आपके नेताओं की गुंडागर्दी के कारण पूरे देश में जितने भी गम्भीर गुनाह हुए हैं उसमें 45 प्रति गुनाह आपकी नाक के नीचे हुए हैं। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की 20 हजार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, आप किस विकास की बात करते हैं। क्या लोग आपको चुनकर इसलिये बैठाते हैं। आपके एक नेता ने कानपुर में छात्रों की पिटाई की। पुलिस ने जुल्म किया। इस गुंडागर्दी की राजनीति को देश अब स्वीकार नहीं करेगा। नेताजी आपके कारनामे कैसे हैं, उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। श्री मोदी ने कहा, ''अब सपा में भी दो खेमे हो गये हैं। एक का नाम है, समाज विरोधी पार्टी और दूसरे का नाम है सुखवादी पार्टी। नेताजी आपकी वजह से राममनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा होती होगी।''

उन्होंने लखनऊ से सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि लखनऊ को देखकर उन्हें वाजपेयी और उनका नेतृत्व याद आता है। उनसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन पिछले कुछ वर्षो से यहां ऐसी सरकारें रही हैं जिनके कारनामों के कारण जो लखनऊ अदब के लिये जाना जाता था वहां अब तहजीब पर तहबाजारी हावी हो गये हैं। बदमाशों का बोलबाला है और गोमती नदी नाले में तब्दील हो गयी है।

श्री मोदी ने कहा कि वाजपेयी कहते थे कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। समृद्ध भारत का सपना तभी पूरा होगा जब समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव तय होगी। अगर भारत का भाग्य बदलना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करनी होगी। गरीबों शोषितों का कल्याण करना है तो उसकी शुरुआत इस विशाल प्रदेश से करनी होगी। एक बार उत्तर प्रदेश शक्तिशाली बन गया तो देश को ताकतवर बनने में देर नहीं लगेगी।

उन्होंने कहा, ''निराशा में डूबे नेता देश को ऊपर नहीं उठा सकते। मैं आशा से भरा हुआ व्यक्ति हूं। मेरी पार्टी आशा से भरी है। भाजपा का लोकतंत्र तो देखिये कि मुझ जैसे पिछड़ी जाति के घर में पैदा हुए और चाय बेचकर जिंदगी चलाने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। दलितों, शोषितों और वंचितों...आने वाला दशक आपका है।''

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस देश को लूट रही है। श्री सिंह ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए केन्द्र में भाजपा-नीत सरकार चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे भाजपा की झोली में प्रदेश की सभी 80 सीटें डालें। इस रैली को पूर्व सेनाध्यक्ष श्री वी.के. सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, सुश्री उमा भारती, श्री लालजी टंडन, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री हुकुम सिंह, श्री उदित राज ने भी संबोधित किया। ■

हुंकार रैली, मुजफ्फरपुर (बिहार)

''देश का भला नहीं कर सकता तीसरा मोर्चा''

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे मोर्चे में शामिल नेताओं को चुनावी खिलाड़ी बताते हुए कहा कि उसमें शामिल लोग चुनाव का माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं।

गत 3 मार्च को बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित हुंकार रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि क्या तीसरे मोर्चे वालों ने कभी किसी का भला किया है। ये छह महीने या एक साल पहले कहीं नजर आते थे। श्री मोदी ने तीसरे मोर्चे में शामिल नेताओं के बारे में कहा कि जब चुनाव का बिगुल बजता है, तभी ये जागते हैं और फिर पांच साल सो जाते हैं। ये चुनावी खिलाड़ी चुनाव का माहौल तो बिगाड़ सकते हैं, पर कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे में वे दल शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है। कभी वे कांग्रेस के लालच में फंसकर काम करते हैं तो कभी सीबीआई से डरकर काम करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि चाहे वह कांग्रेस या तीसरा मोर्चा हो उन्होंने वादे तो बहुत किए पर क्या कोई निभाया है और गरीबों की परवाह की है। वामदल सहित 11 दलों को साथ लेकर तीसरे मोर्चे के गठन पर टिप्पणी करते हुए श्री मोदी ने कहा सार्वजनिक जीवन में हिप्पोक्रेसी (ढोंग) नहीं चलती है।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश की समस्याओं का हल ढूंढ़ना और उनके विरोधियों की प्राथमिकता है श्री मोदी का विकल्प ढूंढ़ना और वे इसमें लगे हुए हैं। यह जो संकुचित मानसिकता है वह देश का कभी भी भला नहीं कर सकती है। उन्होंने राजग को राष्ट्रीय विकास गठबंधन की संज्ञा दी तथा राजग में लोजपा और राष्ट्रीय समता विकास पार्टी का स्वागत करते हुए कहा कि इसका विस्तार हो रहा है और यह बढ़ता ही जाएगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के बारे में कहा कि इससे उनको परेशानी हो रही है तथा यह और भी बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बनिया और ब्राह्मण की पार्टी मानने वाले ये लोग आज उसके द्वारा पिछड़ी जाति के एक बेटे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से चौंक गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला दशक हिंदुस्तान में दलितों, पीड़ितों, शोषितों और आदिवासियों के विकास और उनकी रक्षा का दशक होगा।

हाल में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले और उनके साथ मंच पर मौजूद लोजपा अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे राजग छोड़कर गए थे, पर उसके बाद कहीं और कभी भी उनसे मुलाकात हुई तो प्यार से मिले। श्री मोदी ने कहा कि लेकिन उनके साथ कभी श्री पासवान की अखबार में फोटो छपने पर वे डरे नहीं और न कोई ढोंग किया।

उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमने तो वैसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं। भोजन के टेबिल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के बीच हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिप्पोक्रेसी के

लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। जनता गलतियों को माफ कर सकती है पर जनता हिप्पोक्रेसी को कभी भी माफ नहीं कर सकती।

पिछले वर्ष 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित हुंकार रैली की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उस रैली में राजनीतिक द्वेष के कारण निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक के बाद एक बम धमाके ने पटना की धरती को लहुलूहान कर दिया, उन बम धमाके के घाव भारत के लोकतंत्र के सीने पर लगे थे। वे बमों के घाव हिंदुस्तान की भाईचारा और एकता और सद्भावना पर लगे थे।

पटना में आयोजित इस रैली को श्री मोदी द्वारा संबोधित किए जाने के पूर्व हुए सिलसिलेवार धमाकों में छह लोगों की मौत हो गयी थी। श्री मोदी ने कहा कि तबाही करने वाले जितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लें, पर इतने बड़े हमले के बाद भी शांति, एकता और भाईचारे का दर्शन बिहार के लोगों ने उन्हें कराया, उसके लिए इस धरती और यहां के लोगों को प्रणाम करते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि शांति, एकता और सद्भावना के बिना यह देश विकास और प्रगति नहीं कर सकता है। शांति, एकता, भाईचारा, सदभावना की नींव पर ही विकास की इमारत बनने वाली है। उन्होंने कहा कि किसी को उनसे और किसी को भाजपा से ऐतराज हो सकता है। लोकतंत्र में उनको विश्वास न हो और उन्हें अच्छा भी लगता होगा कि इन धमाकों ने इनका खेल पूरा किया, लेकिन भाजपा के नेताओं को सुरक्षा मिले न मिले पर बेगुनाह नागरिकों को क्यों मारा जा रहा है।

इस रैली में पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं लोजपा अध्यक्ष श्री राम विलास पासवान, रालोसपा नेता श्री उपेन्द्र कुशवाहा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकिशोर यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे ■

गुलबर्ग रैली (कर्नाटक)

कांग्रेस का काम, 'देश तोड़ो, दल तोड़ो और दिल तोड़ो'

कर्नाटक के गुलबर्ग में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। श्री मोदी ने कर्नाटक की जनता से अपील की कि अगर हर समस्या से निजात पाना है तो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना होगा। गत 28 फरवरी को गुलबर्ग के मैदान में आयोजित सभा में श्री मोदी ने कहा कि यहां पर आई जनता का

मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि, जैसे मानो गुलबर्ग में केसरिया समंदर लहरा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि, 2014 के चुनाव से पहले भाजपा की आंधी चल रही है और आंधी के बाद जो सुनामी आएगी उससे कांग्रेस पार्टी बच नहीं पाएगी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 10 जनपथ को लेकर मोदी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 नंबरी गांधी देश को बांटने की राजनीति करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस ने हमेशा तोड़ो और राज करो, बांटो और वोट बैंक बनाओ की राजनीति की है।

इसके साथ ही श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना राज्य के गठन पर कहा कि, तेलंगाना का गठन हो ये बात भाजपा भी चाहती थी लेकिन, कांग्रेस ऐसी डॉक्टर है जो, बच्चे को तो जन्म दिला देती है लेकिन, मां को मार देती है। श्री मोदी ने तेलंगाना के गठन पर कहा कि, भाजपा चाहती थी कि स्वस्थ बच्चा पैदा हो और मां भी सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना बनाने वालों को बधाई देते हैं, सैंकड़ों लोगों की शहादत के चलते तेलंगाना बना है ना कि, कांग्रेस ने तेलंगाना का गठन किया है। श्री मोदी

ने कहा कि, तेलंगाना के लिए कई सालों तक लोगों ने जेलों में जिंदगी गुजारी और सीने पर गोली खाई है, ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। इसके साथ ही श्री मोदी ने कांग्रेस पर सीमांध्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि, सीमांध्र भी हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है लेकिन, कांग्रेस ने उसको अनाथ छोड़ दिया है। श्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है क्योंकि, कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वो सीमांध्र के लोगों के आंसू पोंछने के लिए वहां जाएंगे और उनके हृदय पर जो घाव लगे हैं उन पर मरहम लगाने का काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि, मैं हैदराबाद, तेलंगाना और सीमांध्र से कहना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से आप पर जो जुर्म हुआ है उसे मैं समझता हूं और ये केवल 100 दिन का सवाल है। देश की जनता बंटवारे की राजनीति करने वाली कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी।

श्री मोदी ने कर्नाटक के विकास को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि, कर्नाटक के कई इलाके विकास की राह तक रहे हैं, कर्नाटक की सरकार ने आजतक यहां कुछ नहीं किया है। श्री मोदी ने रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सूबे के मुख्यमंत्री के सिद्धरमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि, रेल मंत्री की रेल ठप्प पड़ी है और मुख्यमंत्री का कारोबार ठप्प पड़ा है। श्री मोदी ने अपनी कांग्रेस पर बांटने की राजनीति करने का आरोप बार-बार लगाया। श्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है वोट बैंक की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति और भाई-भतीजे वाद की राजनीति करना। उन्होंने कहा कि, जनता दुखी रहे, गरीब-गरीब रहे लेकिन उनकी सरकार सलामत रहेद्य देश ने 60 साल तक उनको (कांग्रेस) झेला है। 60 साल में देश कहां तक पहुंच जाता यहां तक कि, जो देश हमारे बाद आजाद हुए वो हमसे आगे पहुंच गए लेकिन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चलते हमारा देश पिछड़ता ही जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि, चुनाव सामने है लेकिन, कांग्रेस अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले देश को बांटा और दिल्ली में बैठ गए, फिर भाषा और प्रांत की राजनीति कर झगड़े करवा दिए और भाई-भाई को लड़वा दिया, फिर राज्यों के बीच पानी को लेकर लड़ा दिया, गांव और शहरों को लड़ा दिया और दलों के टुकड़े करा दिए। श्री मोदी ने कहा कि दल को तोड़ो, देश को तोड़ो और दिल को तोड़ो यही कांग्रेस का काम रहा है। वहीं, गुलबर्ग के मैदान में उमड़े जनसमूह को लेकर श्री मोदी ने कहा कि, मैदान भले ही छोटा पड़ गया हो लेकिन, उनका दिल बहुत बड़ा है और, अपने दिल वो कर्नाटक की जनता को जगह देंगे। इसके साथ ही युवाओं का आह्वान करते हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगर उन्हें अपने जीवन में बदलाव, रोजगार, सम्मान, गौरव और अवसर चाहिए तो, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना होगा। क्योंकि, ना तो कांग्रेस ने युवाओं के लिए कभी कुछ किया है और ना ही कभी कुछ करेगी तो, ऐसी पार्टी की क्या जरूरत है। श्री मोदी ने कांग्रेस को देश पर बोझ बताते हुए कहा कि, 2014 के चुनाव में बीजेपी एक संकल्प लेकर चल रही है जो लोग बोझ बन गए हैं और जो किसी का भला नहीं कर सकते, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते ऐसे लोगों को देश से बाहर करना है।

इसके साथ ही श्री मोदी ने कहा कि, आज तक देश में जो जहर फैलाया गया है उस जहर को शिवरात्रि के दिन शिवजी ने पी लिया है। भाजपा को वोट देने की अपील के साथ श्री मोदी ने कहा कि मैं देश की जनता को पल-पल और पाई-पाई का हिसाब दूंगा देश की जनता किसी भी समय मेरा हिसाब मांग सके उस इरादे के साथ काम करूंगा। कर्नाटक की लोकसभा चुनाव में भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक हिंदुस्तान की राजनीति को नया आयाम दे सकता है और, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में कर्नाटक अपना योगदान दे क्योंकि, कांग्रेस से मुक्ति बिना महंगाई, भ्रष्टाचार, दुराचार, महिलाओं की सुरक्षा और नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। ■

जगरांव रैली (पंजाब)

''भ्रष्टाचार की एबीसीडी कांग्रेस की पहचान बन गई''

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को पंजाब में लुधियाना के पास जगरांव में एक रैली को संबोधित किया। यहां अपने करीब आधे घंटे के भाषण में श्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि पार्टी अब लोगों की आंख में धूल झोंकने की बजाए मिर्ची भी झोंक रही है। उनका इशारा तेलंगाना विधेयक पर कांग्रेस से निष्कासित एक सांसद के लोकसभा में मिर्ची स्प्रे करने की घटना की तरफ था।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने भ्रष्टाचार पर दूसरे दलों पर आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'जब भ्रष्टाचार की पूरी एबीसीडी कांग्रेस की पहचान बन गई हो, तब कांग्रेस के नेताओं की ओर से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्य राजनीतिक दलों पर अंगुली उठाने पर मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है।'

श्री मोदी ने कहा, 'जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब कोई दूसरी पार्टी नहीं थी और केवल कांग्रेस थी जिसका शासन संसद से पंचायत तक था। उस समय उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं तब 15 पैसा ही गांव तक पहुंच पाता है। क्या यह 'पंजा' रुपये को मिटाने और इसे 15 पैसे में बदलने के लिए इस्तेमाल हो रहा था।'

इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि, 'अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तब वह इस शीर्ष सीट पर 'चौकीदार' के रूप बैठेंगे और 'पंजा' को सरकारी खजाने पर अपना साया नहीं पड़ने देंगे।'

श्री मोदी ने एक रैंक, एक पेंशन के मुद्दे पर भी कांग्रेस की आलोचना की। पूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक, एक पेंशन' मंजूर करने में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने ने कांग्रेस पर सशस्त्र बलों के साथ 'धोखाधड़ी' करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी के भ्रष्टाचार से लड़ने की वकालत की खिल्ली उड़ायी।

गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' की बहुप्रतिक्षित मांग को मंजूर कर लिया था और इस मद में 500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार पहले के बजट में इसे लेकर क्यों नहीं आई, जबकि वह पिछले 10 साल से सत्ता में थी। श्री मोदी ने कहा, 'दिल्ली में बैठी सरकार हमेशा सशस्त्र बलों के साथ धोखाधड़ी करती है। इससे पहले कई बार कांग्रेस के वित्त मंत्री एक रैंक एक पेंशन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन कभी इसे पूरा नहीं किया गया।'

उन्होंने कहा, 'चूंकि मैं इस बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने इस बारे में घोषणा की है, लेकिन यह आपके साथ धोखा है। क्या कांग्रेस पार्टी कभी भी ईमानदार रही है, उनके पास 2004 से 2014 तक 10 बजटों में ऐसा करने का मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।'

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने पंजाब में भाजपा अकाली गठबंधन को हिन्दू सिख एकता का प्रतीक बताया जिसने कांग्रेस के बांटो और राज करो के खेल को समाप्त किया। श्री मोदी ने कहा कि पंजाब के साथ मेरा और गुजरात का विशेष नाता रहा है। पहले पंच प्यारों में एक गुजरात के द्वारिका थे। पंजाब के किसानों ने कच्छ को

हरा-भरा बनाया, आज कच्छ लहलहा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि गुजरात पर हर हिंदुस्तानी का बराबर हक है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि गुजरात सरकार सिख किसानों के खिलाफ है। कच्छ से

किसी सिख किसान को गुजरात छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, कोई अफसर गलती करेगा, तो वह अफसर जाएगा, सिख किसान नहीं जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में जहां भी जाओ कोई न कोई गुजराती और कोई न कोई सिख जरूर मिलेगा, जो कंधे से कंधे मिलकर विकास कर रहे हैं।

पंजाब की धरती पर भाजपा-शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यहां की सामाजिक एकता का गठबंधन है, हिन्दू और सिख एकता का प्रतीक है...

श्री मोदी ने कहा कि पंजाब की जनता ने स. प्रकाश सिंह बादल में विश्वास किया और विकास की राजनीति पर भरोसा किया और इसलिए दूसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को लाला लाजपत राय की याद नहीं रही, लेकिन स. प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें याद रखा।

मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल, उपमुख्यमंत्री श्री सुखबीर सिंह बादल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यंमंत्री श्री शांता कुमार सहित तमाम नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर मशहूर पंजाबी अभिनेत्री प्रीति सप्रू भाजपा में शामिल हुईं। ■

पूर्वोत्तर (ईटानगर/गुवाहाटी/अगरतला) रैली

''कोई ताकत अरुणाचल को हमसे अलग नहीं कर सकती''

पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार दावा करने का करारा जवाब देते हुए 22 फरवरी को कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत से इस राज्य को अलग नहीं कर सकती है। श्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, असम के सिल्चर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सभाएं की। श्री मोदी ने इस दौरान स्थानीय समस्याओं का उल्लेख करने के साथ ही सत्ता में आने पर

उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया।

राज्य के पासीघाट कस्बे में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, 'राज्य के बहादुर शहीदों के कारण ही देश की पूर्वोत्तर सीमा सुरक्षित है। समय बदल रहा है और चीन को भी अरुणाचल प्रदेश के प्रति अपने रवैए में बदलाव लाना होगा। मैं यहां आपको यह आश्वासन देने आया हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत से अरुणाचल प्रदेश को अलग नहीं कर सकती।' चीन की विस्तारवादी मानसिकता

बांग्लादेश से दो तरह के लोग आते हैं। एक वे हैं जो कट्टरपंथियों की प्रताड़ना के कारण वहां से भागते हैं। दूसरे वे हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत आते हैं। जब दुनिया भर में हिंदुओं की प्रताड़ना होती है तो उनके पास भारत में आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता।'

को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, 'विस्तारवाद के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। विचार विकास का है। किस तरह देश का विकास किया जा सकता है, लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। चीन को अपनी विस्तारवादी मानसिकता से बाज आना होगा।'

श्री मोदी ने कहा, 'पूरब में अरुणाचल प्रदेश पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पश्चिम में गुजरात पर सबसे अंतिम किरण पड़ती है। गुजरात में अस्त होता हुआ सूरज हर शाम यह वादा करता है कि अगली सुबह वह फिर अरुणाचल प्रदेश में आएगा।'

उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश हर रोज देश को जगाता है। राज्य की विपुल जल संपदा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पूरे देश को रोशन कर सकता है। लोग हालांकि बड़े बांधों के खिलाफ हैं, लेकिन छोटे बांध बनाकर राज्य की क्षमता का दोहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की वजह से अरुणाचल प्रदेश के पास विश्व की पर्यावरण राजधानी बनने की संभावनाएं हैं।

श्री मोदी ने नीडो तानिया की मौत पर भी दुख प्रकट किया, जिसकी राष्ट्रीय राजधानी में पिटाई के बाद मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के छात्रों और रोजगार की तलाश में जाने वालों के लिए दिल्ली, बेंगलुरू और चेन्नई जैसी जगहों पर छात्रावास बनने चाहिए।

सिल्चर में श्री मोदी ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ, हिंदू शरणार्थी और 'डी' मतदाता (अपंजीकृत किए गए संदिग्ध) के मामले 60 महीने के भीतर सुलझा लिए जाएंगे।

श्री मोदी ने कहा, 'असम बांग्लादेश की सीमा पर है और गुजरात पाकिस्तान की सीमा से सटा है। जहां असम की सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण होने वाली समस्या को झेलने के लिए विवश किया है, तो पाकिस्तान मेरे लिए गुजरात में समस्याएं खड़ी करता रहता है। अब आपको फैसला लेना है कि आप बांग्लादेश से पीड़ित रहना चाहेंगे या नहीं।' उन्होंने कहा, 'मित्रों मैं आपके लिए आया हूं। मुझ पर एकबार भरोसा कीजिए और मैं यदि सत्ता में आ गया तो मैं असम में हिरासत की प्रणाली को ही खत्म कर दूंगा। सरकार वोट बैंक की राजनीति की खातिर लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि 'डी' मतदाताओं को उनका अधिकार लौटाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश से दो तरह के लोग आते हैं। एक वे हैं जो कट्टरपंथियों की प्रताड़ना के कारण वहां से भागते हैं। दूसरे वे हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत आते हैं। जब दुनिया भर में हिंदुओं की प्रताड़ना होती है तो उनके पास भारत में आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता।' इतना कहकर उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे शरणार्थियों को पूरे देश में बसाया जाना चाहिए न कि केवल असम पर बोझ डालना चाहिए।

अगरतला में 'नव चेतना रैली' को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुशासन और बांग्लादेशी पूर्वोत्तर के लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के सुशासन के कारण पाकिस्तान समस्याओं का सामना कर रहा है।

भारतीय संघ में शामिल होने के त्रिपुरा के पूर्व शासकों के फैसले की सराहना करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन के जैसे संगीतकारों ने अपने काम के जरिए देश में गौरव हासिल किया। श्री मोदी ने कहा, 'गुजरात के लोगों ने भाजपा को तीन बार चुना, लेकिन त्रिपुरा के लोग वाम मोर्चा को कई बार चुनकर भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'वाम मोर्चा हमेशा लोगों को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे उनके पिछलग्गू बने रहें।' ■

आचरण संबंधी एकाकीपन

अरुण जेटली

केन्द्र सरकार ने करीब दो महीने पहले गुजरात में कथित "स्नूप गेट" (लड़की जासूसी मामला) की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने का फैसला किया था। गुजरात सरकार पहले ही जांच आयोग गठित कर चुकी है जो जांच का काम कर रहा है। केन्द्र सरकार का उद्देश्य राजनैतिक है। वह गुजरात की सरकार और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी को उलझन में डालना चाहती है। केन्द्र सरकार द्वारा सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग करने के बावजूद, उसने जिस आयोग का गठन किया है उसमें बदला लेने की द्वेषपूर्ण भावना और अहंकार की बू आती है। पिछले दस वर्षों में अहंकार यूपीए सरकार की विशिष्टता बन चुकी है। अहंकार के कारण राजनैतिक पतन सुनिश्चित होता है। अहंकारियों में नम्रता का अभाव होता है। अहंकार उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से अलग-थलग करता है जो उनके व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।

उस आयोग का क्या हुआ? आयोग की अध्यक्षता के लिए एक के बाद एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आग्रह किया गया। लेकिन उन्होंने राजनीति से प्रेरित इस कार्य के लिए अपनी सेवाएं देने से इंकार कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से आग्रह किया गया। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के काम के लिए वे उपलब्ध नहीं हैं। सरकार अपने आचरण के कारण अलग-थलग पड़ चुकी है क्योंकि कोई भी उसके इस झूठे काम में हाथ नहीं डालना चाहता।

इसी तरह जब लोकपाल के चेयरमैन और उसके सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति गठित की गई, प्रधानमंत्री और जो अन्य लोग चयन समिति के बारे में उनकी राय बांट रहे थे उन्होंने किसी भी जाने-माने नाम जैसे न्यायमूर्ति वेंकटचैलेया, फली एस नारीमन, सोली जे. सोराबजी, के. पारासरन, के. के. वेणुगोपाल और हरीश साल्वे को चयन समिति में न्यायाधीशों के वर्ग का सदस्य बनाने की स्वीकृति नहीं दी। जब जांच समिति नियुक्त की गई सरकार तीन सरकारी वकीलों में से एक या अधिक की नियुक्ति करना चाहती थी और उसने उनके नामों का सुझाव दिया था। श्रीमती सुषमा स्वराज ने इससे इंकार कर दिया।

श्री फली एस. नारीमन और न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस जांच समिति का हिस्सा बनने से इंकार कर चुके हैं। उनका मानना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वह इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के चयन के इरादे से नहीं थी। अब यह स्पष्ट है कि लोकपाल जैसी संस्था को उसके अस्तित्व में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। जब प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त व्यक्ति जांच और चयन कार्य से जुड़ने से इंकार कर रहे हैं और सरकार के इरादों पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उसका आचरण सम्बन्धी एकाकीपन सिद्ध हो गया है।

मैंने 20 जनवरी 2014 और 30 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने पत्र में उनसे अनुरोध किया था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम अधिनियम के विपरीत हैं। इसमें चयन समिति और जांच समिति के कामकाज को हड़प लिया गया है। खासतौर से जांच समिति केवल क्लर्की वाला काम करने तक सीमित रह गई है। मेरी आपत्तियों पर विचार किये बिना ही उनकी अनदेखी कर दी गई। मैंने दलील दी कि कार्मिक विभाग ने जांच समिति और चयन समिति के अधिकार छीन लिए हैं। चयन समिति की किसी भी बैठक में चयन के मानदंड तय नहीं किए गए। लोकपाल के सदस्यों और चेयरमैन के लिए ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। आवेदनों के साथ समझौता किया गया और लॉबिंग की गई।

श्री फली एस. नारीमन और न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस जांच समिति का हिस्सा बनने से इंकार कर चुके हैं। उनका मानना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वह इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के चयन के इरादे से नहीं थी। अब यह स्पष्ट है कि लोकपाल जैसी संस्था को उसके अस्तित्व में आने से पहले ही नष्ट कर दिया गया है। जब प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त व्यक्ति जांच और चयन कार्य से जुड़ने से इंकार कर रहे हैं और सरकार के इरादों पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उसका आचरण सम्बन्धी एकाकीपन सिद्ध हो गया है। ■

(लेखक राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं)

सबसे बड़ा चुनावी उत्सव

✍ हृदयनारायण दीक्षित

भारत उत्सवप्रिय राष्ट्रीयता है। यहां अनेक उत्सवों की जुगलबंदी है- बसंत की मधुगंधा हवाएं हैं, रंगपर्व होली और तेजस्वी नवसंवत्सर का उल्लास। इन्हीं उत्सवों के बीच दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्री महोत्सव की भी शुरुआत हो गई। निर्वाचन आयोग ने कल आम चुनाव की घोषणा की। लोकसभा के चुनाव विश्व का सबसे बड़ा उत्सव हैं। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। ऐसा स्वाभाविक भी है। आखिरकार यह राष्ट्र तमाम आंतरिक विभाजक शक्तियों के बावजूद सफल जनतंत्र है। यहां तमाम विविधताएं हैं। संस्कृति एक है, लेकिन अनेक भाषाएं, अनेक पंथिक आस्थाएं, अनेक रीति-रिवाज, रंग-रूप और तमाम क्षेत्रीयताएं भी हैं। यह उत्सव बड़ा दिलचस्प है। दलतंत्र की बेचैनी सत्ता है। प्रत्यक्ष रूप में दो वास्तविक गठबंधन हैं- राजग और संप्रग। तीसरा गठबंधन है नहीं, लेकिन अनेक वरिष्ठ राजनेताओं के प्राण तीसरे मोर्चे की कल्पना में ही अटके हैं। चुनाव आयोग ने सीटी अब बजाई है, लेकिन रैलियां, रोड शो, पोस्टर और आरोप-प्रत्यारोप पहले से ही हर नगर, गांव और मोहल्ले में जारी हैं। देश का भाग्य दांव पर है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या आगामी संसद वास्तव में भारतीय जनगणमन की भाग्यविधाता होगी?

> **नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जनअभियान ने श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के चयन का सवाल राष्ट्रीय चिंता बनाया है। मुलायम सिंह, ममता बनर्जी और जयललिता जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी इस प्रश्न को उभारने का काम किया है। डरी कांग्रेस इस सवाल से टकराने से बची है तो भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सकुचाते उम्मीदवार हैं। बावजूद इसके अच्छे सांसद के सवाल ज्यों के त्यों हैं। समाचार माध्यमों खास तौर से अखबारों ने उम्मीदवारों की सादगी, कर्मठता और ईमानदारी जैसे गुणों का वातावरण बनाया है। आम आदमी पार्टी के उदय ने इस वातावरण को गति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार बनाने में भ्रष्ट कांग्रेस का साथ लेने और अन्य कारणों से 'आप' की छवि अब सार्थक दबाव समूह की भी नहीं है। उसे वोट कटवा पार्टी के रूप में ही देखा जा रहा है।**

यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। 81 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। पिछले चुनाव से 10 करोड़ ज्यादा। मतदान केंद्रों की संख्या पिछले चुनाव में सवा आठ लाख थी अब सवा नौ लाख से ज्यादा हो गई है। आयोग ने इस दफा अतिरिक्त सतर्कता दिखाई है। साल 2009 के चुनाव सिर्फ पांच चरण वाले ही थे। इस दफा यूपी के चुनाव ही छह चरण में हैं। पूरे देश के चुनाव नौ चरणों में हैं। इससे सुरक्षाबलों की नियुक्ति, आवाजाही व निर्वाचन कर्मियों की व्यवस्था में सुविधा होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन केंद्र व कई राज्यों की सरकारें चुनाव घोषणा के ठीक पहले तक अनेक घोषणाएं कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण थोक के भाव किए हैं। चुनाव कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकारों के दबाव में होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राच्यों के अधिकारियों से निष्पक्ष काम कराना आयोग के लिए चुनौती है।

लोकसभा चुनाव प्रायः दो परिणाम देता है। पहला संसदीय क्षेत्र की जनता को एक प्रतिनिधि। जनता के हर्ष-विषाद को बोली देने वाला जिम्मेदार प्रवक्ता। दूसरा परिणाम है केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार और एक प्रधानमंत्री। इस दफा के चुनाव में प्रधानमंत्री का मुद्दा ऊपर हो गया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जनअभियान ने श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के चयन का सवाल राष्ट्रीय चिंता बनाया है। मुलायम सिंह, ममता बनर्जी और जयललिता जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी इस प्रश्न को उभारने का काम किया है। डरी कांग्रेस इस सवाल से टकराने से बची है तो भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सकुचाते उम्मीदवार हैं। बावजूद इसके अच्छे सांसद के सवाल ज्यों के त्यों हैं। समाचार माध्यमों खास तौर से अखबारों ने उम्मीदवारों की सादगी, कर्मठता और ईमानदारी जैसे गुणों का वातावरण बनाया है। आम आदमी पार्टी के उदय ने इस वातावरण को गति दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार बनाने में भ्रष्ट कांग्रेस का साथ लेने और अन्य कारणों से

'आप' की छवि अब सार्थक दबाव समूह की भी नहीं है। उसे वोट कटवा पार्टी के रूप में ही देखा जा रहा है। आदर्श सांसद हर निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता और जनआकांक्षा है। भारत के सामने अनेक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं। स्थायी सरकार राष्ट्रीय आवश्यकता है। गठबंधन सरकारें घटक दलों के दबाव में अच्छा काम नहीं कर पातीं। संसदीय प्रणाली में जवाबदेही का सद्‌गुण है तो अस्थायित्व का अवगुण भी। यह प्रश्न संविधान सभा में भी उठा था। डॉ. अंबेडकर ने सभा को बताया था कि यह बात सही है कि संसदीय प्रणाली में अस्थायित्व का खतरा विद्यमान रहता है, लेकिन हमने जवाबदेही को प्राथमिकता दी है।

मतदाता प्रसन्न हैं। वे चुनाव को लेकर अधीर थे। केंद्र सरकार ने बहुत कष्ट दिए। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई ने आमजनों को बहुत रुलाया। सो सरकार बदलने की बेताबी है। विकल्पहीनता के बादल छंट गए हैं। तो भी उमस गहरी है। युवा मतदाताओं की फौज मैदान में है। अब मतदाता ही सम्राट हैं। वे शासक चुनने के विवेक से लैस हैं। 'भारत सर्वोपरिता' का वातावरण है। धनबल, बाहुबल और जातिबल के पुराने नुस्खे दगा दे रहे हैं। चुनाव ही गैरजिम्मेदार दल और नेता की पिटाई का उत्सव होते हैं। दलतंत्र स्वाभाविक ही भयग्रस्त है और आमजन मस्त बिंदास। 2014 के चुनाव अभूतपूर्व अवसर हैं।

डॉ. मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल अस्थायित्व के शिकार रहे। संप्रग-1 में वामदलों के दबाव थे तो संप्रग-2 में दक्षिण के दलों ने श्रीलंका से जुड़ी विदेश नीति को भी प्रभावित करने की कोशिश की। 272 सांसदों की संख्या राष्ट्रीय चुनौती है। कांग्रेस इस महत्वाकांक्षा से अलग है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस संख्या का दावा किया है। बेशक क्षेत्रीय दलों के प्रभाव क्षेत्र में राष्ट्रीय दल का प्रभाव बनाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। आखिर एक समय कांग्रेस ही पूरे देश में प्रभावी राष्ट्रीय दल थी। मतदाताओं ने उसे खारिज किया, क्षेत्रीय दलों को जगह मिली। अब क्षेत्रीय दलों से भी निराशा है। भाजपा के लिए क्षेत्रीय निराशा को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में बदलने की चुनौती है।

आम मतदाता के सामने स्थायी सरकार चुनने का सुगम अवसर है, लेकिन अनेक दलों के नेताओं के लिए यहां जीवन-मरण की चुनौती भी है। उत्तर प्रदेश की सपा के सामने अस्तित्व का प्रश्न है। सपा सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। घोषित उम्मीदवार टिकट वापस कर रहे हैं। मुलामय कठोर हो चुके हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं का यक्ष प्रश्न है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सामने आत्मरक्षा का प्रश्न है। चुनाव कांग्रेस को इतिहास की पुरातात्विक सामग्री बना सकते हैं। विद्वान प्रधानमंत्री इतिहास की शरण में जा चुके। चुनौती करुणानिधि के सामने भी हैं। क्या करें? कहां जाएं? दक्षिणपंथी जयललिता वामपंथी रास्ते चली गईं। ममता अन्ना के आशीर्वाद से उत्साहित हैं, लेकिन राहें उनकी भी आसान नहीं हैं। लालू प्रसाद रामविलास की बेवफाई से पीड़ित हैं। रामविलास राजनाथ सिंह की मिठाई खा चुके हैं। वामपंथी काफी अर्से से हलकान हैं। वे पश्चिम बंगाल खोने के बाद से ही विषादग्रस्त थे। ताजा चुनाव संभावनाओं से आशंकित वामदल अवसादग्रस्त भी हैं। नीतीश कुमार के सामने भी अस्तित्व का संकट है। भाजपा, पासवान और लालू तीनों ही उन्हें घेर चुके हैं।

मतदाता प्रसन्न हैं। वे चुनाव को लेकर अधीर थे। केंद्र सरकार ने बहुत कष्ट दिए। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई ने आमजनों को बहुत रुलाया। सो सरकार बदलने की बेताबी है। विकल्पहीनता के बादल छंट गए हैं। तो भी उमस गहरी है। युवा मतदाताओं की फौज मैदान में है। अब मतदाता ही सम्राट हैं। वे शासक चुनने के विवेक से लैस हैं। 'भारत सर्वोपरिता' का वातावरण है। धनबल, बाहुबल और जातिबल के पुराने नुस्खे दगा दे रहे हैं। चुनाव ही गैरजिम्मेदार दल और नेता की पिटाई का उत्सव होते हैं। दलतंत्र स्वाभाविक ही भयग्रस्त है और आमजन मस्त बिंदास। 2014 के चुनाव अभूतपूर्व अवसर हैं।

जनता 15 लोकसभाएं चुन चुकी। अनुभव गहरा गए हैं। इसलिए देश की राजनीतिक संस्कृति बदलने की संभावनाएं हैं। जिम्मेदार और जवाबदेह प्रधानमंत्री व सांसद चुने जाने की उम्मीदें हैं। केंद्र में स्थायी और जवाबदेह सरकार आने की जनअभिलाषाएं भी हैं। सिर्फ इलेक्ट्रानिक मशीन के बटन दबाने मात्र से सोद्देश्य सत्ता परिवर्तन की महाक्रांति घटने जा रही है। ■

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

(साभार- दैनिक जागरण)

भाजपा, कांग्रेस और दलित प्रश्न

डॉ. उदित राज

अक्टूबर, 1997 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के निर्माण के समय से ही मैंने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। उस वर्ष आरक्षण विरोधी पांच आदेश जारी हुए थे और मेरे नेतृत्व में पूरे देश के कर्मचारी, अधिकारी, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक होकर देशव्यापी आंदोलन चलाने में सहयोग किया। इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और हम उनसे मिले। वाजपेयीजी बहुत उदार दिल के थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आरक्षण विरोधी आदेश दूसरी सरकार के समय में हुए थे, तो शिकायत हमसे क्यों? उनके शब्द थे-करे कोई, भरे कोई? हमने आग्रह किया कि विचार तो आपको ही करना है। अंत में उन्हीं की सरकार ने 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन किए और आरक्षण बचाया। भाजपा के प्रति दलितों एवं आदिवासियों का रुख नरम पड़ने लगा था, लेकिन विनिवेश मंत्रालय ने फिर से उन्हें डरा दिया। तमाम सरकारी उपक्रम जैसे मारुति उद्योग का विनिवेश एवं बिक्री शुरू हुआ तो दलित-आदिवासियों को लगा कि उनका आरक्षण समाप्त करने का यह षड्यंत्र है। 2004 में दूर-दूर तक यह आभास नहीं था कि भाजपा लोकसभा चुनाव हारेगी। फील गुड फैक्टर और शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ भाजपा छह महीने पहले ही चुनाव में उतर गई और अंत में हार हुई।

भाजपा का आकलन गलत नहीं था, लेकिन एक बात का उसे अहसास नहीं हुआ कि दलित समाज का कर्मचारी, अधिकारी एवं बुद्धिजीवी का प्रभाव खुले रूप से नहीं दिखता, लेकिन उसकी मारक क्षमता बहुत होती है। यही कारण भाजपा की हार का रहा, जो अभी तक तमाम चुनावी विद्वान विश्लेषकों की नजर में नहीं आ सका। कांग्रेस के नेतृत्व में जब संप्रग सरकार बनी तो उसे अहसास था कि दलितों के लिए कुछ करना है और उसकी शुरुआत भी की। डॉ. मनमोहन सिंह ने फौरन सभी विभागों को पत्र लिखा कि सभी खाली पद वर्ष 2005 तक भर दिए जाएं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का वादा किया गया। 2004 में मंत्रियों की एक समिति शरद पवार के नेतृत्व में बनाई गई-यह विचार करने के लिए कि कैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जा सकता है। 2006 में पीएमओ में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया। इनका उद्देश्य सरकारी स्तर पर निजी क्षेत्र में भागीदारी के उपाय सुझाना था। दूसरी तरफ देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन जैसे सीआइआइ, एसोचैम आदि से वार्तालाप करके उन तमाम संभावनाओं को खोजना भी था कि वे अपने यहां दलितों-आदिवासियों को भागीदारी दें। इन्होंने तमाम वायदे किए, जैसे दलित उद्यमी तैयार करने और कोचिंग, ट्यूशन, स्कॉलरशिप आदि की बातें हुई। हालांकि कुछ विशेष नहीं किया जा सका। उल्टे कुछ दलितों को आगे करके बयानबाजी कराई जाने लगी कि दलित उद्यमी बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। वास्तव में जो थोड़े बहुत दलित उद्यमी अपने बूते पैदा हुए थे उन्हीं की मार्केटिंग की जाने लगी। इस प्रकार कांग्रेस सरकार का यह कार्यक्रम ध्वस्त हो गया।

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्यसभा में बिल तो पास कराया, लेकिन लोकसभा में यह अभी तक पास नहीं हो सका है। 85वें संवैधानिक संशोधन की पैरवी हमने सुप्रीम कोर्ट में 2006 में

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी और हम उनसे मिले। वाजपेयीजी बहुत उदार दिल के थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आरक्षण विरोधी आदेश दूसरी सरकार के समय में हुए थे, तो शिकायत हमसे क्यों? उनके शब्द थे-करे कोई, भरे कोई? हमने आग्रह किया कि विचार तो आपको ही करना है। अंत में उन्हीं की सरकार ने 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन किए और आरक्षण बचाया।

जीती, लेकिन चार जनवरी, 2011 को लखनऊ हाईकोर्ट ने इसे खत्म कर दिया। वहां हम इसलिए हारे, क्योंकि सरकार मायावती की थी। हालांकि दलित होने के नाते उनकी विशेष जिम्मेदारी थी, लेकिन वह इसे निभा न सकीं। केंद्र सरकार ने दलितों-आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नीति बनाई कि सरकारी योजनाओं में चार प्रतिशत भागीदारी दलितों की होगी, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी संसद सत्र में स्पेशल कंपोनेंट एवं ट्राइबल सब प्लान को लागू करने के लिए कानून बनाना था, लेकिन वह भी नहीं किया जा सका।

मेरे भाजपा में शमिल होने के कई कारण हैं। यह पार्टी न केवल राजनीतिक सत्ता के लिए प्रयासरत है, बल्कि समाज की रक्षा की भी उतनी ही जिम्मेदारी महसूस करती है। गत कई महीनों से देशभर में फैले मेरे प्रमुख सहयोगियों और भाजपा के बीच लगातार वार्तालाप हुए, तमाम मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ, तब जाकर सहमति बनी। मेरे अकेले भाजपा में शामिल होने से उतनी ताकत नहीं मिल सकती थी जब तक कि देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अन्य समर्थकों की सहमति नहीं मिलती। आइआइटी टॉपर लाहिड़ी गुरु का प्रयास है कि भारत में जातिविहीन समाज की स्थापना हो। उनकी मध्यस्थता से 24 नवंबर को नागपुर में बैठक हुई। यहां चिंतन का विषय था हजारों वर्ष से दलित और सवर्ण समाज की दूरी को कैसे खत्म किया जाए?

अंत में सहमति बनी कि दलितों-आदिवासियों को भाजपा मीडिया, उद्योग-व्यापार, ठेका, आपूर्ति आदि में भागीदारी दे। अगर यह हुआ तो जो क्रांति हजारों वर्ष में नहीं हुई वह कुछ सालों में हो जाएगी। भाजपा में मैं इसलिए भी शामिल हुआ कि राष्ट्रीयता की चिंता इसके सिवाय अन्य किसी दल को उतनी नहीं है। सेक्युलरिज्म को पुन: परिभाषित करना होगा। इन तथाकथित सेक्युलरिस्टों को कश्मीर से भगाए चार प्रतिशत पंडितों की याद नहीं आती, लेकिन गुजरात हमेशा इनके दिमाग में रहता है। गुजरात में जो हुआ वह बुरा हुआ, लेकिन गोधरा में जो हुआ वह भी तो अच्छा नहीं था। 1984 में सिखों के साथ जो हुआ वह क्या था? करोड़ों बांग्लादेशी और उसमें से अधिकतर मुसलमान जो भारत में आ रहे हैं उन पर ये क्यों शोर नहीं मचाते? भारत-पाक विभाजन के समय वहां 22 प्रतिशत हिंदू आबादी थी, जो अब महज दो प्रतिशत है, आखिर कहां चले गए वह लोग? बांग्लादेश में 29 प्रतिशत हिंदू हुआ करते थे, अब केवल नौ प्रतिशत रह गए हैं। तस्लीमा नसरीन कहती हैं कि यहां के सेक्युलरिस्ट हिंदू कट्टरवाद पर तो बिफर पड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम कट्टरवाद पर क्यों चुप रहते हैं? भाजपा और संघ को भी दलितों और आदिवासियों के बारे में विशेष कार्यक्रम तैयार करने होंगे और तभी एकात्म और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। ■

(लेखक वरिष्ठ दलित नेता हैं)

(साभार- दैनिक जागरण)

दलित नेता उदित राज भाजपा में हुए शामिल

गत 24 फरवरी 2014 को वरिष्ठ दलित नेता श्री उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री राज का भाजपा में स्वागत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर एक समुदाय भी पिछड़ा और हाशिए पर बना रहता है तो देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासन में अनुसूचित जाति को कोई लाभ नहीं मिला, जबकि भाजपा उनके उत्थान के लिए सतत् प्रयास करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हाल में तीन दलित नेताओं को राज्यसभा भेजा है। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी श्री उदित राज ने कहा कि कांग्रेस के शासन में दलितों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जबकि भाजपा का रवैया अधिक सहानुभूतिपर्ण रहा है। ■

भाजपा के प्रति बढ़ती अनुकूलता

राजनाथ सिंह सूर्य

पांच विधानसभा चुनाव के बाद दिसम्बर में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 2014 के निर्वाचन के बाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल तो होगा लेकिन उसे 100 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जनवरी के अंत तक उसे 200 के आसपास सीटें प्राप्त होने का जो अनुमान था, वह निर्वाचन की तिथि घोषित होते होते सवा दो सौ के लगभग आ ही गया है। जिस रफ्तार से भाजपा को मिलने वाली सीटों में बढ़ोतरी का अनुमान किया जा रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भाजपा द्वारा 272 के अधिक सीटें प्राप्त करने का दावा अस्वाभाविक नहीं है।

पार्टी के सर्वोच्च नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तो इन अनुमानों के बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ भाजपा के अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। क्या कारण है भाजपा के प्रति बढ़ती अनुकूलता का? क्या इसलिए कि उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की शंखनाद रैलियों में अपार जनसमूह उमड़ रहा है या फि इस कारण की कांग्रेस अपनी छवि धूमिल करती जा रही है, या फिर धूमकेतु आम आदमी दल से लोगों को भारी निराशा हुई है। आगामी लोकसभा में दलीय स्थिति की संभावना का जो पहला आंकलन आया था उसमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों को लगभग साढ़े तीन सौ सीटें मिलने का आंकलन पेश किया गया था। इस आंकलन से उत्साहित भाजपा विरोधी मानसिकता वालों ने तीसरे मोर्चे या क्षेत्रीय दलों के फेडरल गठबंधन की सत्ता की संभावनाओं का आंकलन शुरू किया था।

यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बनेगी। एक और तथ्य विचारणीय है, वह है नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता निरंतर किए जा रहे आक्षेपों के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। नवीनतम अनुमान के अनुसार देश की 57 प्रतिशत अवाम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जिन दो अन्य को यह अनुमान में शामिल किया गया है उनमें से एक राहुल गांधी के पक्ष में महज तेरह प्रतिशत और केजरीवाल के पक्ष में तीन प्रतिशत लोगों के होने का अनुमान लगाया गया है।

नई दिल्ली में चौदह दलों के नेताओं ने एक मंच पर भुजबंधन कर यह साबित करने का प्रयास किया था कि वे ''एक हैं''। यद्यपि इस ''एकता'' के खोखलेपन के बारे में किसी को भ्रम नहीं था, तथापि भाजपाविरोधी मानसिकता वालों को जो आम आदमी पार्टी की वानरी कलाबाजियों से निराश हो चुके थे, यह आशा बंधी थी कि कांग्रेस के समर्थन से एक बार फिर देवगौड़ा या गुजराल के समान कोई सरकार लौट सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी की जोरदार आकांक्षाएं अभिव्यक्त की जाने लगी थीं। यह अस्वाभाविक नहीं था। लेकिन विधिवत चुनाव की तारीखों की घोषणा कि पूर्व भाजपा को अकेले सवा दो सौ और कांग्रेस को 73 सीटें तथा शेष को 200 के आसपास सिमट जाने के आंकलन ने राजनीतिक अराजकता की स्थिति से देश को निकालने की मतदाताओं की मानसिकता सुदृढ़ होते जाने का संकेत दिया है। चुनावी संभावनाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों से भाजपा में पैठ बनाने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। दलित नेता उदितराज शामिल हो चुके हैं, बिहार की कुशवाहा समाज पार्टी का समझौता और रामविलास की पार्टी का समझोता और रामविलास की पार्टी का समझौता प्रयास भाजपा के प्रति अनुकूलता का प्रतीक है।

इस मानिसकता का एक महत्वपूर्ण कारण जहां नरेंद्र मोदी की छवि को सांप्रदायिक, विघटनकारी आदि साबित करने के प्रयासों की पोल न्यायिक फैसलों से पोल खुलते जाना है वहीं नरेंद्र मोदी का विकास के मुद्दे पर डटे रहना है। नरेंद्र मोदी ने भारत में अपूर्व क्षमता के प्रति विश्वास पैदा किया और इस क्षमता को विकास के लिए उपयोग की प्रतिबद्धता अवाम में विश्वास पैदा किया। उनको हत्यारा, जहरीला, खूनी राजनीति आदि साबित करने वाले अभियानों का मुंहतोड़ जवाब देने की उनकी क्षमता और जिस मुस्लिम वर्ग को उनके प्रति भयभीत करने के प्रयास को अपने विकास के एजेंडे से जो जवाब दिया गया उसकी गुजराती बानगी लोगों में

यह विश्वास पैठाने में सफल रही कि मोदी देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी का यह फार्मूला भी लोगों को ग्राह्य हुआ कि भारत और भारतीयों में सभावनाओं और क्षमता का अभाव नहीं है, सुशासन का अभाव है। उनका सुराज का नारा संभावनाओं की समझ बढ़ाने में काफी कामयाब हुआ। इसलिए अवाम में यह भावना पैदा हुई कि भारत बीमार नहीं कमजोर है। बीमार को खिचड़ी खिलायी जाती है लेकिन कमजोर को पौष्टिक पदार्थ की आवश्यकता है। इसलिए अवाम में खिचड़ी सरकार के बजाय एकदलीय सरकार के लिए आग्रह बढ़ता जा रहा है जो आकलनकर्ताओं की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आ रहा है। अब सवाल यह नहीं पूछा जा रहा कि यदि किसी एकदल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? कौन किससे मिलेगा बल्कि यह कि यदि भाजपा पूर्ण बहुमत से कुछ पीछे रह गई तो किस किस की उसके साथ आने की संभावना है। अभी तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एकाध अत्यंत छोटे दलों को छोड़कर देशव्यापी ख्याति रखने वाले अकालीदल और शिवसेना ही भाजपा के साथ है जिस फरवरी के अंत में आकलनकर्ताओं ने 236 सीटें मिलने की संभावना बताई है, जो पूर्ण बहुमत से बहुत कम नहीं है। यदि यह मान लिया जाय कि सजग को कुल इतनी ही सीटें मिलेंगी तो बहुमत से कुल 24 सीटें ही कम रहती हैं, जिसका सहयोग मिलना अत्यंत सहज है। अतएव यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बनेगी। एक और तथ्य विचारणीय है, वह है नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता निरंतर किए जा रहे आक्षेपों के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। नवीनतम अनुमान के अनुसार देश की 57 प्रतिशत अवाम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। जिन दो अन्य को यह अनुमान में शामिल किया गया है उनमें से एक राहुल गांधी के पक्ष में महज तेरह प्रतिशत और केजरीवाल के पक्ष में तीन प्रतिशत लोगों के होने का अनुमान लगाया गया है।

जिन केजरीवाल को राहुल गांधी से भी अधिक लोकप्रिय माना गया था उनके प्रति आकर्षण में इस भारी गिरावट के कारण दायित्व से भागने और अनर्गल प्रलाप को माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने और उसके निर्वाचन को जो दृढ़ संकल्प पेश किया है, वह भी उनके प्रति बढ़ते आकर्षण का कारण है लेकिन इन सबक मूल में है अवाम की एकदलीय सुदृढ़ सरकार के प्रति बढ़ती आकांक्षा। भारतीय जनमानस यह समझ चुका है कि भ्रष्टाचारवाद परिवारवाद और ढकोसलायी सेक्युलरवाद, के मायाजाल में उसने बहुत कुछ खो दिया है। इस अहसास ने उसे एकदलीय सरकार के लिए प्रेरित किया है। साथ ही ऐसे नेतृत्व के लिए भी जो ढोंग के बजाय सभी के प्रति समान दृष्टिकोण और स्पष्ट दृष्टा हो।

नरेंद्र मोदी उसकी आकांक्षा के अनुरूप धनी व्यक्तित्व के रूप में अपनी आभा प्रगट करने में सफल हैं। लेकिन भाजपा को अन्य दलों के भगोड़ों और अन्य उन लोगों की जो राजनीति में नहीं रहे, पैठ बनाने का सावधानी से विवेचना करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो इस भीड़ में भाजपा के निष्ठावान निष्क्रिय हो जाय। ■

मोतिहारी में गौवंश विकास सम्मेलन आयोजित

मोतिहारी (बिहार) के टाउन हॉल में गाय के संरक्षक, सुरक्षण और विकास के लिए गौवंश विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्घाटन सांसद श्री राधा मोहन सिंह ने किया तथा इसमें विधान परिषद सदस्य श्री गिरिराज सिंह और श्री ह्दयनाथ सिंह शामिल हुए। श्री ह्दयनाथ सिंह ने बैठक में उपस्थित व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परम्परा में गाय को अपनी माता समान माना जाता है और यह समय की मांग है कि हम गाय को संरक्षण प्रदान करें। बैठक में जिन अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया, उनमें भाजपा गौ विकास प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री मयंकेश्वर सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री सचिन्द्र सिंह तथा श्री कृष्ण नंदन पासवान शामिल थे।■

आर्थिक समृद्धि का रास्ता है मोदीनामिक्स

✍ कंचन गुप्ता

भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आपको हार्वर्ड की डिग्री या एनिमल स्प्रिट की आवश्यकता नहीं है। यदि हार्वर्ड में मिला ज्ञान या एनिमल स्प्रिट को स्वतंत्र करने से काम चलता तो अर्थव्यवस्था ऐसे बुरे हाल में न होती जिसके गवाह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं जो भारत की परेशानी का दोष दुनिया पर डाल रहे हैं। लेकिन यह यथार्थ हार्वर्ड शिक्षित वित्त मंत्री को भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी का मजाक उड़ाने से नहीं रोकता है। आर्थिक मामलों में नरेन्द्र मोदी की कम जानकारी का मजाक उड़ाते हुए पी. चिदम्बरम ने बड़े भद्दे तरीके से कहा है कि आर्थिक मामलों में उनकी जानकारी को एक डाक टिकट के पीछे लिखा जा सकता है। नरेन्द्र मोदी ने अपनी शैली में इसका जोरदार जवाब दिया है। पिछले सप्ताह नयी दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित अर्थशास्त्रियों, बिजनेस कार्यकारियों तथा राजनयिकों के इंडिया इकोनोमिक कन्वेंशन, 2014 में उन्होंने कहा कि उनका ज्ञान इस मामले में और भी कम है तथा उसे डाक टिकट के पीछे भी नहीं लिखा जा सकता है।

लेकिन यह व्यंग्य उस समय समाप्त नहीं हुआ जब नरेन्द्र मोदी ने अपने आर्थिक एजेंडे पर बात रखी। भारत की आर्थिक अवनति को उलटना तो दूर उसे रोकने में भी विफल रहने वाले वित्त मंत्री भले ही मुख्यमंत्री का मजाक उड़ायें जो न केवल राज्य के आर्थिक प्रगति के रास्ते पर चले हैं, बल्कि ऐसे राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके राष्ट्र के प्रति योगदान ने भयानक, ईर्ष्या को जन्म दिया है। हालांकि किसी टिप्पणी से मुख्यधारा मीडिया को कष्ट हो सकता है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे कांग्रेस द्वारा 2004 में प्राप्त 'अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं।

पी. चिदम्बरम की टिप्पणी से यह तथ्य भ्री नहीं छिपाया जा सकता है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कहे जाने वाले मनमोहन सिंह को गलती से 1991-1996 के आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है जो आईएमएफ के पैकेज के अंतर्गत लागू किये गये थे तथा आंशिक रूप से वे पीवी नरसिम्हाराव के एजेंडे द्वारा संचालित थे जिसमें नेहरूवादी समाजवाद को अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि आज उन्होंने अकेले दम पर भारत की प्रगति कथा का अन्त कर दिया है। बेशर्म प्रधानमंत्री नेहरू वंश परिवार के कारण अपने पद पर हैं और अनजान बन कर अत्यधिक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नाक के नीचे भयानक लूट जारी है और उनसे नीति या परिकल्पना के रूप में अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में सोचने की आशा नहीं की जा सकती है। यदि इसकी उम्मीद की जाये तो भारत की महान रस्सी खड़ी करने वाली ट्रिक भी कल्पना नहीं रह जायेगी।

इस सप्ताह नयी दिल्ली में तीन अलग-अलग अवसरों पर बोलते हुए नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यस्था को परेशान करने वाली समस्याओं के अनोखे समाधान पेश किये जो पुरानी शैली की बेहतरीन सामान्य समझदारी का आधार हैं जिसे राजनीतिक प्रतिबद्धता कहा जा सकता है। यह दोनों बातें उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती हैं जो नेहरू वंश परिवार की मेज से गिरे टुकड़े खाने पर जीवित रहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने समस्याओं पर जो प्रतिक्रिया की थी और भारत की आर्थिक विकलांगता के लिए जो समाधान सुझाये थे वे निरर्थक थे। एक समय था जब मनमोहन सिंह की सोच को खांचों से अलग सोच समझा

नयी दिल्ली में तीन अलग-अलग अवसरों पर बोलते हुए नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यस्था को परेशान करने वाली समस्याओं के अनोखे समाधान पेश किये जो पुरानी शैली की बेहतरीन सामान्य समझदारी का आधार हैं जिसे राजनीतिक प्रतिबद्धता कहा जा सकता है। यह दोनों बातें उन लोगों की समझ में नहीं आ सकती हैं जो नेहरू वंश परिवार की मेज से गिरे टुकड़े खाने पर जीवित रहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने समस्याओं पर जो प्रतिक्रिया की थी और भारत की आर्थिक विकलांगता के लिए जो समाधान सुझाये थे वे निरर्थक थे।

जाता था। उन्होंने बहुत समय पहले एनिमल स्प्रिट को स्वतंत्र करने की बात कही ही, लेकिन बादल में पता चला कि यह भावना भी भावी संकट के समाधान के लिए बहुत कमजोर थी।

खांचे से बाहर सोचने के लिए बड़ी सोच की आवश्यकता होती है। यह सोच आज और कल की सोच से अलग सामान्य समझ और प्रतिबद्धता से जुड़ी है जिसे आप अपनी इच्छा से राजनीतिक प्रतिबद्धता कह सकते हैं। नरेन्द्र मोदी का यह कहना ठीक है कि प्रशासन कोई रोकेट विज्ञान नहीं है और यह केवल उद्देश्य की स्पष्टता तथा कार्रवाई में निष्ठा है। एक बार इनको लागू कर देने पर बाकी चीजें नीति तथा क्रियान्वयन योग्य कार्यक्रमों के रूप मे स्वयं आगे बढ़ती हैं तथा समस्याओं के तत्कालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन समाधान निकालती है। केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की बात करना काफी नहीं है ताकि निवेश प्राप्त किया जा सके।

यह विश्वास पैदा करने के लिए अच्छे प्रशासन की शर्त प्रारम्भिक है और इसके लिये राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास की आवश्यकता है। यह विश्वास ऐसी फर्जी योजनाओं द्वारा नहीं पैदा हो सकता है जैसी योजनाओ द्वारा पैसे की बर्बादी संप्रग शासन में दिखायी पड़ी है।

जब नरेन्द्र मोदी ढांचागत संरचनाओं में निवेश, विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, कृषि क्षेत्र का पोषण करने, सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा इन सबको अद्यतन तकनीक से जोड़ने की बात करते हैं तो वे वास्तव में मूलभूत रूप से कोई नयी बात नहीं कर रहे होते हैं। दस मिलियन लोगों को हर साल रोजगार देने के लिए ये सब काम करने आवश्यक हैं। लेकिन वे सारी चीजों से अलग इसलिए दिखते हैं कि उनकी आवाज गंभीरता से सुनी जाती है और वे जो कुछ कहते हैं वह उनके अनुभव पर आधारित है। वे लोकाराजकता की बात नहीं करते हैं जो कांग्रेस की समझ से वोट दिलाती है, पर बर्बादी भी लाती है। वे खोखले अधिकारों की बात नहीं करते हैं, बल्कि श्रम के गौरव तथा रोजगार पर जोर देते हैं। वे खैरात की बात करने के बजाय संपदा बनाने तथा उद्यमी भावना और युवा भारत की उम्मीदों से लाभ उठाने की बात करते हैं।

बहुत से लोग तर्क देंगे कि चुनावों के पहले यह बात करना व्यावहारिक नहीं है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतियोगिता योग्य बनें तथा चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहें। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार भी संरक्षणवाद की बात कर रहे हैं तथा विदेशी प्रतियोगिता का सवाल उठाते हैं, भले ही वे चाहे जिस राजनीतिक पार्टी के हों। यह परंपरागत समझदारी माना जाता है।

परंपरागत बुद्धि को अस्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिये और नरेन्द्र मोदी के पास ठीक यही साहस है। उन्होंने बड़ी व छोटी भारतीय कंपनियों से प्रतियोगी होने तथा विश्व बाजार व प्रतियोगिता के प्रति अपना भय छोड़ने को कहा है। उन्होंने दुष्टिकोण बदलने, निकट वाली चीजों से आगे देखने, चुनौतियों को अवसर की तरह लेने तथा तकनीक मं निवेश करने की बात कही है। वे भविष्य की राजनय को आर्थिक व व्यापार सबंधो पर आधारित करना चाहते हैं।

जिस व्यक्ति की जानकारी एक डाक टिकट में फिट हो सकती है वह अगली पीढ़ी की तकनीक की बात करता है, जैव-प्रौद्योगिकी व पर्यावरण-प्राद्योगिकी में निवेश की पैरवी करता है। यह उन लोगों की मूर्खता सिद्ध करना हो जो उनका मजाक उड़ाते हैं। नरेन्द्र मोदी छोटी तस्वीर, छोटी विवरणी, नट-बोटों, आदि पर विचार नहीं करते क्योंकि यह उन लोगों का काम है जिनको नीति क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह चीज इसी तरह होनी चाहिये। एक प्रधानमंत्री को वास्तव में बडी तस्वीर पर विचार करना चाहिये तथा ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य तय करने चाहिये जिनको पूरा करना असंभव लगता हो। प्रमाण के लिए 19 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में उनके भाषण पर विचार करें जिसमें उन्होंने अपरिवर्तनीय शहरीकरण से निबटने के लिए 100 नये शहरों, सुपरफास्ट ट्रेनों व प्रतिबद्ध गलियारों, नये एक्सप्रेसवे व राजमार्गों, उच्च प्रौद्योगिकी से संचालित अधिक उपज वाली खेती तथा अनेक बड़ा चीजों की बात कही है।

उनका मजाक उड़ाना था यह पूछना आसान है कि इसके लिये पैसा कहां से आयेगा? इस सवाल का जवाब सरल है। एक बार निवेशकों का विश्वास बहाल हो जाने पर भारत की कहानी एक बार फिर वैश्विक आकर्षण का केन्द्र बन जायेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पोखरन-2 के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद भाजपा नीत राजग संसाधन एकत्र करने तथा विशाल परियोजनायें आगे बढ़ाने में सफल हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बड़े विचारों का क्रियान्वित करने में छोटी चीजों को बाधा नहीं बनने देते थे। उस समय बहुत काम हुआ था। प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद फिर बहुत काम होगा। ■ (साभार-पायनियर)

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं)

वक्त की नब्ज : नए भारत की नींव

✍ तवलीन सिंह

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है साफ होने लग गया है कि 1977 वाले आम चुनाव के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है भारत वर्ष के लिए। उस चुनाव में इस देश के मतदाताओं को फैसला करना था तानाशाही और लोकतंत्र के बीच और मत दिए उन्होंने लोकतंत्र के लिए। इस बार ऐसे लग रहा है कि भारत के मतदाताओं को चुनना होगा अतीत और भविष्य के बीच, पुराने भारत और नए भारत के बीच। पुराने भारत को जो जिंदा रखना चाहते हैं राजनीतिक दल उन में गिन सकते हैं हम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और हाल में बने तीसरे मोर्चे को। इन राजनीतिक दलों की नजरों में भारत को सबसे बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी से क्योंकि मोदी एक नए भारत की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं।

बातें जब यह लोग करते हैं सांप्रदायिकता की तो इस इरादे से कि विषय बदल जाएं और उनकी कमजोरियां कम दिखें मोदी के नए सपने के सामने। मोदी ने आर्थिक विचारों को मुख्य मुद्दा बना रखा है अपने चुनाव आंदोलन का क्योंकि जानते हैं कि मायूसी कितनी है देश में बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण। आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं उनके प्रतिद्वंद्वी क्योंकि वे जानते हैं कि अगर सत्ता मिलती है उन्हें दोबारा तो वही समाजवादी आर्थिक नीतियां पेश करेंगे जिन्होंने एक ऐसा भारत बनाया है जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों को।

आर्थिक दिशा बदलने की बातें भी नहीं कर सकते ये लोग क्योंकि वामपंथी विचारधारा उनके लिए धर्मग्रंथ है। आम आदमी पार्टी इन में सबसे नई है लेकिन इस दल के भी बुनियादी आर्थिक विचार वही हैं जो कांग्रेस के रहे हैं नेहरूजी के जमाने से। इसलिए जब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके साथी तो इसका सारा दोष डालते हैं मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे बड़े उद्योगपतियों पर। ऐसा नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते हैं सो हाल में केजरीवाल साहिब ने उन पर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह कि वह भी अंबानी और अदानी के पुर्जे हैं। लेकिन धीरे-धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि ऐसी बातों को कोई असर नहीं हो रहा है मतदाताओं पर क्योंकि सर्वेक्षण बता रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ रही है अगर किसी की तो मोदी की। ऐसा क्यों हो रहा है? निराशा के माहौल में क्यों मोदी की तरफ लोग आशान्वित होकर देख रहे हैं? मेरी राय में वह इसलिए क्योंकि मोदी गरीबी हटाने की बातों को छोड़ कर बातें कर रहे हैं संपन्नता और समृद्धि की। एक नए भारत की। इस नए भारत के बारे में उन्होंने पिछले हफ्ते दिल्ली के एक सम्मेलन में उद्योगपतियों और व्यापारियों से विस्तार से बातें की। पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नजरों में भारत की शक्ति किन चीजों से आती है। यहां इन्होंने अंग्रेजी के तीन शब्दों का इस्तेमाल किया। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड। यानी लोकतंत्र, जनसंख्या और बाजार। फिर उन्होंने समझाया कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद क्यों भारत की गाड़ी अटक सी गई है और यहां उन्होंने अभाव बताए देश के इन शब्दों में। सुशासन, आस्था और सिद्धांतों के। इन में से प्राथमिकता मोदी देते हैं सुशासन को, स्पष्ट किया उन्होंने कि अगर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के तो प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान देंगे। मोदी के नए भारत वाले सपने में आम आदमी के जीवन में सुधार लाने को भी अहमियत दी जाती है खासतौर पर देहातों में जहां बिजली, पानी जैसी बुनियादी सेवाओं का गंभीर अभाव है। गुजरात से उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आम आदमी के जीवन में सिर्फ बिजली के आने से कितना फर्क पड़ता है। कहा

निराशा के माहौल में क्यों मोदी की तरफ लोग आशान्वित होकर देख रहे हैं? मेरी राय में वह इसलिए क्योंकि मोदी गरीबी हटाने की बातों को छोड़ कर बातें कर रहे हैं संपन्नता और समृद्धि की। एक नए भारत की। इस नए भारत के बारे में उन्होंने पिछले हफ्ते दिल्ली के एक सम्मेलन में उद्योगपतियों और व्यापारियों से विस्तार से बातें की। पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी नजरों में भारत की शक्ति किन चीजों से आती है। यहां इन्होंने अंग्रेजी के तीन शब्दों का इस्तेमाल किया। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड। यानी लोकतंत्र, जनसंख्या और बाजार।

उन्होंने 'आत्मा होनी चाहिए गांव की लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए शहरों की।' शहरीकरण को मोदी एक अवसर के रूप में देखते हैं समस्या के रूप में नहीं।

मुझे जो उनकी बातों में से सबसे अच्छी बात लगी वह थी कि हमको मिल कर तय करना चाहिए कि गांधीजी की 150वीं जयंती तक हम देश भर में सफाई का विशाल अभियान चलाएंगे। ऐसा अभियान अगर जन आंदोलन बन जाता है तो संभव है कि भारत की 80 फीसद बीमारियां गायब हो जाएंगी क्योंकि यह पैदा होती हैं गंदगी से। लेकिन इस देश के एक ही राजनेता ने कभी बात की है सफाई की और वह थे गांधीजी। उनके बाद सफाई का जिक्र तक नहीं करते हैं हमारे राजनेता मालूम नहीं क्यों? अगर मोदी करने को तैयार हैं तो बहुत बड़ी बात होगी।

मोदी ने अपने इस भाषण में और कई बातें की। शिक्षा पर, देश की सुरक्षा पर, नौजवानों के दिलों में भारतीय होने का गर्व पैदा करने पर और इन बातों से एक नए, संपन्न भारत का सपना बुना। इन सब बातों का विश्लेषण करना नामुमकिन है लेकिन यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं उनका यह भाषण जो मेरी राय में उनके सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से है। एक घंटा लंबा भाषण है और मैंने जब पूरा सुना और सुनने के बाद उसका विश्लेषण किया तो समझ में आने लगा मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का राज।

मेरा मानना है कि मोदी लोकप्रिय इसलिए हुए हैं क्योंकि जहां बाकी राजनेता बातें करते हैं गरीबी हटाने की और गरीबों को राहत देने की, मोदी बातें कर रहे हैं संपन्नता लाने की। समृद्ध भारत का यह सपना बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, ऐसे समय जब हर तरफ निराशा ही निराशा फैली हुई है। इस निराशा में अगर कोई बड़ा राजनेता आकर कहता है कि भारत में उसको संभावनाएं ही संभावनाएं दिखती हैं तो क्यों न उसकी बातें इस देश के आम आदमी को अच्छी लगने लगे। ■

(लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

(साभार- जनसत्ता)

पूर्व भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण नहीं रहे

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंगारू लक्ष्मण का 1 मार्च 2014 को हैदराबाद में निधन हो गया। वे 74 साल के थे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी शोक-संदेश

श्री बंगारू लक्ष्मण जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर गहरा दु:ख पहुंचा है। श्री बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। संगठनात्मक स्तर पर विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वाहन करते हुए श्री बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। यही नहीं वे सांसद रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री रहे। श्री लक्ष्मण ने अपने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में दलित उत्थान और वंचितों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किया। वैसे तो उनका पूरा जीवन जन-कल्याण व लोक सेवा के कार्यों में ही गुजरा। श्री बंगारू लक्ष्मण एक दलित नेता के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से देश ने जहां एक दलित नेता को खोया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से शोक की इस घड़ी में दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ■

कल्याण सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 3 मार्च 2014 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। ■

कांटों भरी राजनीति

स्वप्न दासगुप्ता

एक टीवी चैनल द्वारा किए गए स्टिंग आपरेशन ने चमक खोते भारत में विकास कर रहे चंद सेक्टरों में से एक में शामिल कतिपय कुटिल खिलाड़ियों का खुलासा कर दिया है। यह सेक्टर है ओपीनियन पोल उद्योग। इस कथित खुलासे की वाकई जरूरत थी। हो सकता है कि इस खुलासे के बाद अपेक्षाकृत अधिक पेशेवर और सही तरह से किए गए सर्वेक्षणों का कोई तरीका निर्मित हो। यदि ऐसा हुआ तो आर्डर देने पर तैयार किए जाने वाले सर्वेक्षणों (जैसा कि दावा किया जा रहा है) की तुलना में अधिक भरोसेमंद सर्वेक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपीनियन पोल के आधार पर सत्ता प्रतिष्ठान इस नतीजे पर पहुंचता हो कि कौन सा दल आम चुनाव में विजयी होगा। मेरे अनुभव में केवल दो बार दिल्ली का प्रतिष्ठान (जो आम तौर पर बेहद कुशाग्र होता है) इस बारे में अनुमान लगाने में असफल रहा कि लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा। सबसे पहले 1977 में और फिर 2004 में। कुछ-कुछ ऐसा ही 1996 में भी देखने को मिला था जब अनिश्चितता के वातावरण में कोई अंदाज लगाना कठिन था।

अब जब अगली लोकसभा के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी होने में कम समय शेष रह गया है तब दिल्ली के सरकारी खेमे में सोच यह है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एक माह पहले अटकलें सीटों की संख्या को लेकर लगाई जा रही थीं, लेकिन आज चर्चाएं मोदी कैबिनेट की संरचना को लेकर हो रही हैं। एक ऐसी बेरहम दुनिया में जहां देश के सत्ताधारी दल के शीर्ष समूह में पहुंचने की होड़ मच जाती हो, वंशवाद और कांग्रेस को विपक्षी बेंचों की ओर खिसका दिया गया है। कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक पूर्व संपादक ने पिछले सप्ताह मेरे सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस अपनी सम्मानजनक हार सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही है। वैसे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। एक्टिविस्ट ब्रिगेड का एक वर्ग अभी भी यह महसूस करता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चौंकाने वाला प्रदर्शन करेगी और गांधीनगर से अपना घर दिल्ली स्थानांतरित करने के मोदी के अभियान को रोकने में कामयाब रहेगी। इसके साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इस भरोसे से चिपके हुए हैं कि भाजपा खुद ही कुछ क्षेत्रीय दलों के दबाव में मई में अपने घर में तख्तापलट को अंजाम देगी और एक कहीं अधिक स्वीकार्य प्रधानमंत्री को सामने लाने का काम करेगी।

अब जब अगली लोकसभा के गठन की औपचारिक अधिसूचना जारी होने में कम समय शेष रह गया है तब दिल्ली के सरकारी खेमे में सोच यह है कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एक माह पहले अटकलें सीटों की संख्या को लेकर लगाई जा रही थीं, लेकिन आज चर्चाएं मोदी कैबिनेट की संरचना को लेकर हो रही हैं। एक ऐसी बेरहम दुनिया में जहां देश के सत्ताधारी दल के शीर्ष समूह में पहुंचने की होड़ मच जाती हो, वंशवाद और कांग्रेस को विपक्षी बेंचों की ओर खिसका दिया गया है। कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक पूर्व संपादक ने पिछले सप्ताह मेरे सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस अपनी सम्मानजनक हार सुनिश्चित करने के लिए जूझ रही है।

मैं दिल्ली के खास घेरे तक पहुंच रखने वाले उन मुट्ठीभर लोगों में शामिल हूं जो यह विश्वास करते हैं कि कोई चुनाव तब तक नहीं जीता जाता है जब तक वोटों की गिनती खत्म न हो जाए। मोदी को शुरुआती बढ़त मिल सकती है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाने और प्रचार का अभियान अंतिम चरण में पहुंच जाने के बाद ही नतीजों को लेकर कोई अर्थपूर्ण आकलन किया जा सकता है। इससे भी अधिक, मैं अंतिम समय तक जुझारू संघर्ष करने की कांग्रेस की क्षमता को भी कम करके नहीं आंकता हूं। जब राजनीतिक बेदर्दी की बात आती है तो कांग्रेस अपनी प्रतिद्वंद्वी भाजपा से मीलों आगे नजर

आती है। तेलंगाना के गठन संबंधी विधेयक पारित करने के मामले में हम यह देख भी चुके हैं।

वास्तव में पिछले कुछ सप्ताहों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कांग्रेस आपातकालीन योजनाएं बनाने में जुटी हुई है। उसकी पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से हर हाल में मोदी को रोकना है। इसके लिए वह अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रामविलास पासवान के यू-टर्न और उनके फिर से राजग में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के भीतर यह सोच है कि मोदी को रोकना संभव नहीं हो सकता है। अब तो ऐसी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है कि स्थितियां और खराब हो सकती हैं।

वास्तव में पिछले कुछ सप्ताहों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कांग्रेस आपातकालीन योजनाएं बनाने में जुटी हुई है। उसकी पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से हर हाल में मोदी को रोकना है। इसके लिए वह अपने तरकश के हर तीर का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि रामविलास पासवान के यू-टर्न और उनके फिर से राजग में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के भीतर यह सोच है कि मोदी को रोकना संभव नहीं हो सकता है। अब तो ऐसी फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही है कि स्थितियां और खराब हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में कांग्रेस दूसरे विकल्प की ओर मुड़ती दिखाई दे रही है। यह विकल्प है-जितना संभव हो, नई मोदी सरकार के लिए जीवन उतना ही कठिन बना दिया जाए।

इन परिस्थितियों में कांग्रेस दूसरे विकल्प की ओर मुड़ती दिखाई दे रही है। यह विकल्प है-जितना संभव हो, नई मोदी सरकार के लिए जीवन उतना ही कठिन बना दिया जाए। स्वास्थ्य सचिव के तबादले, एक प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख को अकारण सेवाविस्तार देने और यहां तक कि अंतिम क्षणों में एक राज्यसभा सांसद के नामांकन के फैसलों पर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। नौकरशाही के पदों, समितियों, सरकारी निकायों और दूसरे ऐसे पदों को आनन-फानन में भरा जा रहा है जहां केंद्र सरकार अथवा उसके राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया है। इन पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा रही है जो यदि कांग्रेस समर्थक नहीं हैं तो उनकी छवि मोदी विरोधी की तो है ही। नामों को मंजूरी देने की हड़बड़ी इस कदर है कि खुफिया एजेंसियां यह शिकायत कर रही हैं कि उन्हें छानबीन करने के लिए पूरा समय नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय में जो नियुक्तियां अगले छह माह में या उसके बाद होनी हैं उन्हें आचार संहिता लागू होने के पहले ही भरा जा रहा है। शासन के अपने लंबे अनुभव के साथ कांग्रेस यह जानती है कि अंतिम समय में लिए जा रहे इन फैसलों में अनेक को नई सरकार के हाथों पलटा जा सकता है, लेकिन उसकी सोच यह है कि एक मंत्री के कामकाज की खामियों की तलाश करने में महीनों और कभी-कभी वर्षों लग सकते हैं। इस लिहाज से नई सरकार को कुछ ऐसे क्षेत्रों में कठघरे में खड़ा किया जा सकता है जिन पर सरकार का ध्यान न हो और इस आधार पर कुशासन के आरोप उस पर लगाए जा सकते हैं।

जिन लोगों की राजनीतिक याददाश्त अच्छी है उन्हें याद होगा कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार को 1998 में अपने शुरुआती दिनों में नौकरशाही के फंदे का सामना करना पड़ा था। उदाहरण के लिए जिस प्याज संकट के चलते 1998 में भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था वह नैफेड द्वारा रचा गया था, जिसका नियंत्रण कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के हाथ में था। इसी तरह पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भी वाजपेयी सरकार ऐसे राजनयिकों के असहयोग से जूझी थी जिनका अपना एजेंडा वाजपेयी सरकार के खिलाफ था।

अगर मोदी 2014 में अपनी शुरुआती बढ़त को निर्णायक लहर में तब्दील करने में सफल रहते हैं तो वह नि:संदेह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि यह विश्वास कर लेना अभी जल्दबाजी होगी कि अगली सरकार की कमान संभालने वाला व्यक्ति भारत के लिए नया सबेरा लेकर आएगा। जा रही सरकार ने अगले शासन के लिए कुछ ऐसे स्थानों पर जाल बिछा दिए हैं जिनके बारे में लोगों को शायद ही अंदाज हो।

साफ है कि अगले प्रधानमंत्री के लिए पहला दिन ही चुनौतियों से भरा होगा।■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

(साभार- दैनिक जागरण)

"नरेन्द्र मोदी- ए विक्टिम ऑफ मैनीपुलेशन्स" का लोकार्पण

ऐसे प्रकाशनों से गलत धारणाएं समाप्त होंगी : अरुण जेटली

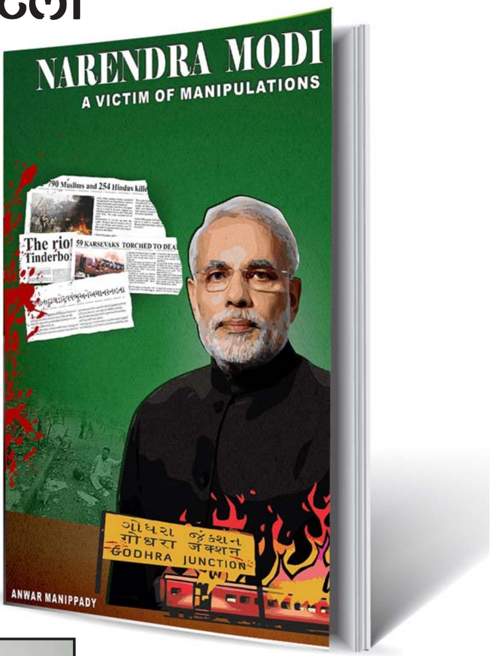

गत 27 फरवरी 2014 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अनवर मनीपदी द्वारा अंग्रेजी में लिखित 'नरेन्द्र मोदी- ए विक्टिम ऑफ मैनीपुलेशेन्स'' का लोकार्पण किया। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर श्री अरुण जेटली के साथ राज्यसभा में उनके अन्य सहयोगी श्री एम. रामा जॉइस, श्री तरुण विजय और श्री प्रकाश जावडेकर भी साथ थे।

इस कार्यक्रम में ठीक 12 वर्ष पूर्व 2002 में गोधरा ट्रेन कोच त्रासदी तथा इसके बाद हुए उपद्रवों में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनिट का मौन धारण रखा गया।

इस अवसर पर श्री अरुण जेटली ने अपने भाषण में दर्शकों को श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ किए गए सिलसिलेवार निंदा की उन बातों का स्मरण कराया जो मीडिया के एक वर्ग, अन्य लोगों और निहित स्वार्थों ने 2002 से लगातार करते रहे। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि श्री मोदी के खिलाफ की गई इस प्रकार की मनगढ़ंत निंदा गाथाओं का स्वयं ही पर्दाफाश भी हो गया। अंत में, उन्होंने आशा व्यक्त की कि श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ यदि अभी भी कोई गलत धारणाएं मौजूद होंगी तो इस प्रकार की पुस्तकों से दूर करने में मदद मिलेगी।

पुस्तक के लेखक श्री अनवर मनीपदी ने अपने भाषण में विस्तार से श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ बुने गए जाल की चर्चा भी की, जबकि यह श्री नरेन्द्र मोदी का ही अथक प्रयास रहा जिससे गुजरात में लोगों का विकास और कल्याणकारी कार्य हुए एवं अन्ततः इससे अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं बेहतर खुशहाल स्थिति में पहुंचा दिया।

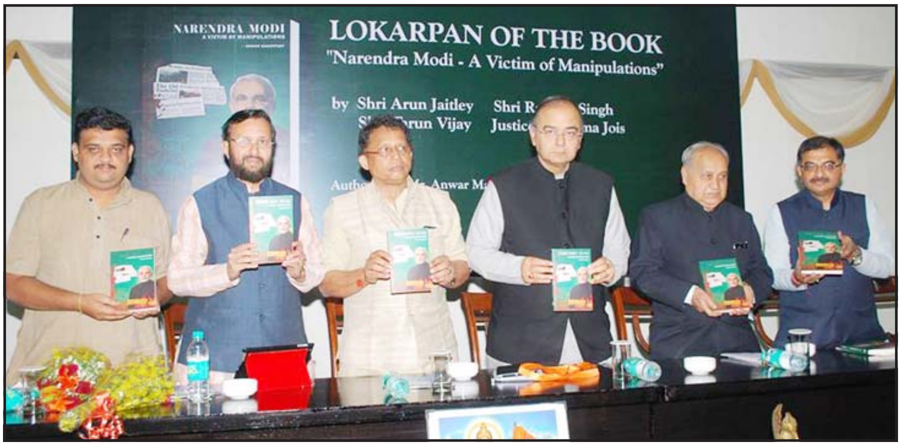

श्री तरुण विजय इस अवसर पर दूसरे वक्ता थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरी पीड़ा हुई थी।

अंत में पूर्व जस्टिस और राज्यसभा सदस्य श्री एम. रामा जॉइस ने अपने समापन भाषण में इस बात की चर्चा की कि श्री नरेन्द्र मोदी ने जीवन की विलासिताओं को त्यागकर एक शासक के रूप में अपना 'धर्म' निभाया है और वे पूरी तरह से इस बारे में खरे उतरते हैं।

पुस्तक का प्रकाशन संयुक्त सहयोग से विजनेश्वर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर इन पालिटी, गुलबर्गा और समृद्ध साहित्य पब्लिकेशन हाउस, बंगलुरू (कर्नाटक) ने किया है। इस अवसर पर पुस्तक के प्रकाशक हर्ष ने भी अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान की। ■

उपवास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश

राज्य सरकार किसानों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार पर आपदा की घड़ी में मदद न करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसानों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

प्राकृतिक आपदा ने राज्य में जमकर तबाही मचाई है और बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। केंद्र सरकार से मदद के लिए विशेष पैकेज न मिलने के विरोध में 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी बंद के आहवान के साथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार ने उपवास रखा।

उपवास के दौरान श्री चौहान ने कहा कि राज्य के किसानों को संकट की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी होगी। भले ही विकास कार्य रोकना पड़े, लेकिन किसानों को मदद दी जाएगी। केन्द्र सरकार संकट के दौर में सियासत कर अपने संवैधानिक दायित्व से भी मुंह चुरा रही है।

राज्य सरकार की केंद्र सरकार से पांच मांगें हैं जिनको लेकर गुरुवार को आधे दिन का राज्यव्यापी बंद और सरकार ने उपवास रखा। सरकार की मांग है कि प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। ओला प्रभावित किसानों को तात्कालिक राहत के लिए केन्द्र सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज अविलंब दे। प्रदेश के चना की समर्थन मूल्य पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की केंद्र सरकार पहल करे। फसल बीमा योजना को व्यावहारिक बनाया जाए। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के चावल को बासमती की मान्यता दें।

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को आंसू बहाने की जरुरत नहीं है सरकार उनके साथ है। केंद्र सरकार से वे राहत पैकेज मांग रहे हैं, मगर केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जनता का पैसा है और वह पैसा जनता के लिए देने को तैयार नहीं हैं।

श्री चौहान ने कहा कि वे राहत राशि के लिए दिल्ली गए मगर प्रधानमंत्री ने मुलाकात का समय नहीं दिया। उनका कहना है कि वे एक बार फिर अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली जाकर अपना हक मांगेंगे।

उपवास स्थल पर पहुंचकर विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री को किसानों की मदद के लिए राहत राशि सौंपी। उपवास पर मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के मंत्री व पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

भाजपा के आहवान पर 6 मार्च को प्रदेशव्यापी बंद पूरी तरह सफल रहा। इस बंद के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और लोगों को चाय नाश्ते तक के लिए तरसना पड़ा। इस बंद से शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन सेवा, पेट्रोल पंप आदि को दूर रखा गया।

मालूम हो कि राज्य में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश से 10 हजार से अधिक गांव में बड़े पैमाने पर फसल चौपट हुई है, राज्य सरकार ने दो हजार करोड़ की राशि किसानों की मदद के लिए मंजूर की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये की मदद मांगी, जिसे पूरा नहीं किया गया।

राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नर्मदा घाटी विभाग सहित अन्य शासकीय विभाग के कर्मचारी भी आगे आए हैं। शासकीय चिकित्सकों के संगठन ने दो माह का महंगाई भत्ता लगभग तीन करोड़ 30 लाख रुपये की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। ■

जन. वी.के. सिंह तथा अन्य कई प्रख्यात पूर्व-सैनिक शामिल हुए भाजपा में

गत 12 मार्च 2014 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पूर्व-सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह तथा कई अन्य प्रख्यात पूर्व-सैनिक ले. जन. पी. चौधरी, ले. जन. ए.के. चोपड़ा, ले. जन. देवराज सिंह, ले. जन बाहिरी, ले. जन. पी.सी कटोच, ले. जन. वी.के. चतुर्वेदी, ले. जन. सतवीर सिंह यादव, एवीराम बोरडोलोई, मेजर-जनरल एन.बी. सिंह, एयर-कोमोडर विक्रम सिंह, मेजर जनरल आई.के.चोपड़ा, जनरल एस.डी.अवस्थी, मेजर-जनरल डा. एस.एस. चौहान, मेजर जनरल आर. सिंह, मेजर जनरल एस.पी. सिन्हा, मेजर-जनरल के.के. बक्शी, एयर-कोमोडर एस. एस.त्यागी, एयरकोमोडारआर. नाथ, एयर-कोमोडोर हर्मेश, एयर कोमोडोर वी.के. गुप्ता, एयर कोमोडोर एन.के.शर्मा, एयरकोमोडेर वी.के. कौशिक, कोमोडोर अवस्थी, ब्रिगेडियर सी.एम आद्या, ब्रिगेडियर वीर पाल सिंह, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर, ब्रिगेडियर आर.ए.सिंह, डीआईजी एस.पी.एस तोमर, डीआईजी वी.पी. सिंह ने भाजपा मुख्यालय, 11, अशोक रोड, नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने अपने सम्बोधन में इन पूर्व-सैनिकों का स्वागत करते हुए भाजपा के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर रक्षाबलों तथा पूर्व सैनिकों के लटके सभी मामलों को क्रियान्वित करेगी जिनमें हथियारों की खरीदारी। विकास, सैनिकों की गरिमा को बढ़ाना आदि शामिल रहेंगे।

अपने सम्बोधन में जन.वी.के. सिंह ने कहा कि हमारी सेना के सैनिक देशभक्त व्यक्ति है और वे सदैव देश के बारे में सेवानिवृत्त होने के बाद भी चिंतित रहते हैं और भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जो अत्यंत देशभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी है, इसी कारण हम भाजपा में शामिल हुए हैं।

जन. विजय कुमार सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी इण्डियन आर्मी आफिसर (1970-2012) सेवा निवृत्ति ली है और वे इण्डियन आर्मी के 26वें सेनाध्यक्ष रहे हैं। श्री विजय कुमार सिंह हरियाणा राज्य के जिला भिवानी के बापोरागांव के रहने वाले हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ से ग्रेजुएशन की तथा वे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी इंफ्रेंट्री स्कूल से हॉनर्स ग्रेजुएट किया, वे फोर्ट बेन्निंग और कार्लाईज-पेनीसिल्वेनिया से युनाइटेड स्टेट्स आर्मी वार कालेज के ग्रेजुएट भी हैं।

11 मार्च 2011 को श्री सिंह को युनाइटेड स्टेट्स आर्मी वार कालेज (2001 के ग्रेजुएट की श्रेणी में) इंटरनेशनल फैलो हॉल ऑफ फेम में संस्थापित किया गया। वे 33वें आफिसर हैं जिन्हें यह गरिमा प्राप्त हुई है। आप्रेशन रेंजर टैब के दौरान अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मैडल, अति विशिष्ट सेवा मैडल, युद्ध सेवा मैडल प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ■

लोकसभा चुनाव-2014 की घोषणा

लोकतंत्र का महापर्व 7 अप्रैल से

चुनाव आयोग ने 16वीं लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव के लिए 7 अप्रैल से 12 मई के बीच नौ चरणों में मतदान संपन्न होंगे और मतगणना 16 मई को कराई जाएगी। इसके साथ ही तीन राज्यों तेलंगाना समेत आंध्रप्रदेश, ओडिशा, सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी होंगे।

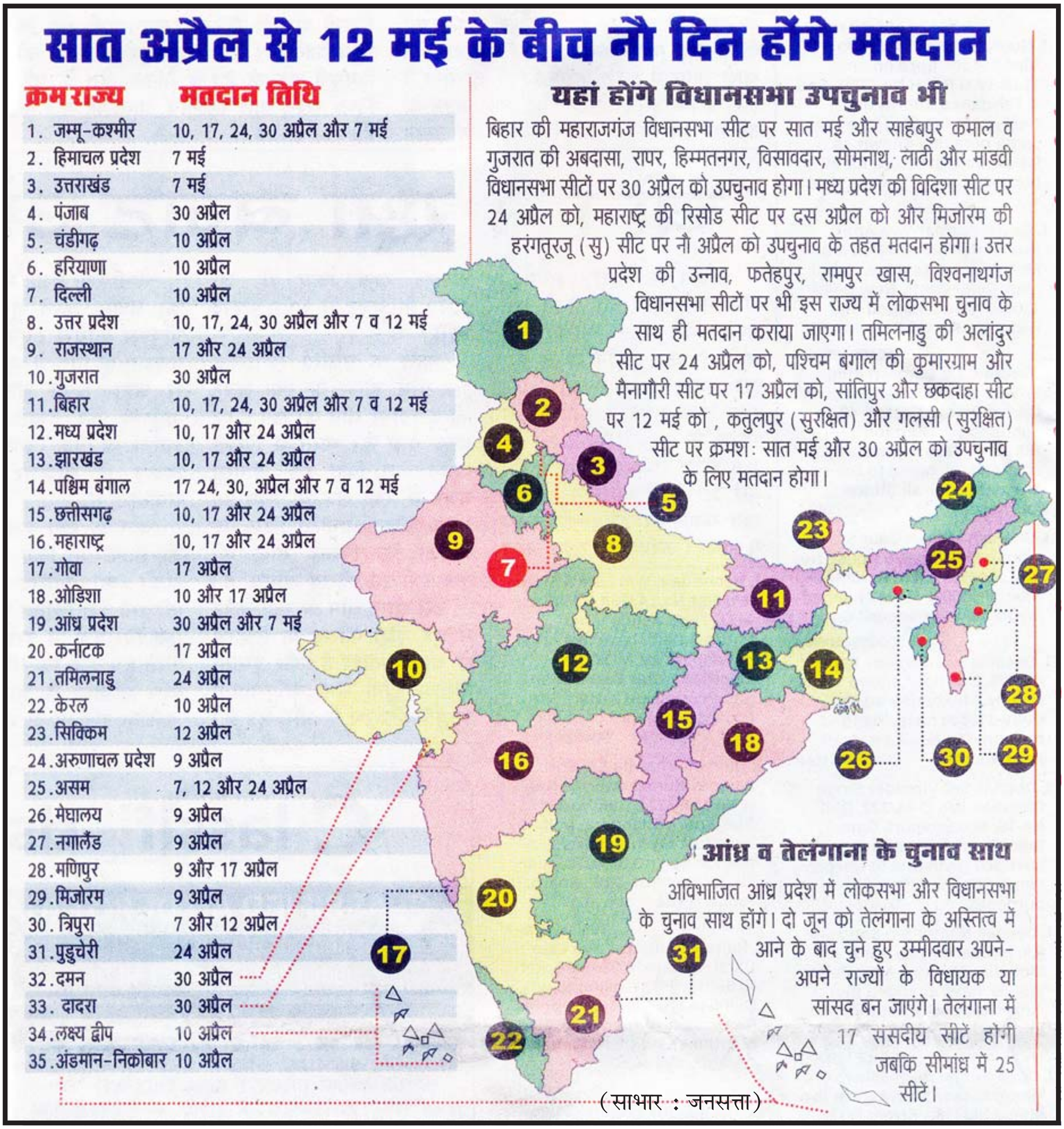

सात अप्रैल से 12 मई के बीच नौ दिन होंगे मतदान

क्रम राज्य	मतदान तिथि
1. जम्मू-कश्मीर	10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 मई
2. हिमाचल प्रदेश	7 मई
3. उत्तराखंड	7 मई
4. पंजाब	30 अप्रैल
5. चंडीगढ़	10 अप्रैल
6. हरियाणा	10 अप्रैल
7. दिल्ली	10 अप्रैल
8. उत्तर प्रदेश	10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 व 12 मई
9. राजस्थान	17 और 24 अप्रैल
10. गुजरात	30 अप्रैल
11. बिहार	10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 व 12 मई
12. मध्य प्रदेश	10, 17 और 24 अप्रैल
13. झारखंड	10, 17 और 24 अप्रैल
14. पश्चिम बंगाल	17 24, 30, अप्रैल और 7 व 12 मई
15. छत्तीसगढ़	10, 17 और 24 अप्रैल
16. महाराष्ट्र	10, 17 और 24 अप्रैल
17. गोवा	17 अप्रैल
18. ओड़िशा	10 और 17 अप्रैल
19. आंध्र प्रदेश	30 अप्रैल और 7 मई
20. कर्नाटक	17 अप्रैल
21. तमिलनाडु	24 अप्रैल
22. केरल	10 अप्रैल
23. सिक्किम	12 अप्रैल
24. अरुणाचल प्रदेश	9 अप्रैल
25. असम	7, 12 और 24 अप्रैल
26. मेघालय	9 अप्रैल
27. नगालैंड	9 अप्रैल
28. मणिपुर	9 और 17 अप्रैल
29. मिजोरम	9 अप्रैल
30. त्रिपुरा	7 और 12 अप्रैल
31. पुडुचेरी	24 अप्रैल
32. दमन	30 अप्रैल
33. दादरा	30 अप्रैल
34. लक्ष्य द्वीप	10 अप्रैल
35. अंडमान-निकोबार	10 अप्रैल

यहां होंगे विधानसभा उपचुनाव भी

बिहार की महाराजगंज विधानसभा सीट पर सात मई और साहेबपुर कमाल व गुजरात की अबदासा, रापर, हिम्मतनगर, विसावदार, सोमनाथ, लाठी और मांडवी विधानसभा सीटों पर 30 अप्रैल को उपचुनाव होगा। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट पर 24 अप्रैल को, महाराष्ट्र की रिसोड सीट पर दस अप्रैल को और मिजोरम की हरंगतूरजू (सु) सीट पर नौ अप्रैल को उपचुनाव के तहत मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की उन्नाव, फतेहपुर, रामपुर खास, विश्वनाथगंज विधानसभा सीटों पर भी इस राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान कराया जाएगा। तमिलनाडु की अलांदुर सीट पर 24 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल की कुमारग्राम और मैनागौरी सीट पर 17 अप्रैल को, सांतिपुर और छकदाहा सीट पर 12 मई को, कतुलपुर (सुरक्षित) और गलसी (सुरक्षित) सीट पर क्रमशः सात मई और 30 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होगा।

आंध्र व तेलंगाना के चुनाव साथ

अविभाजित आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। दो जून को तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद चुने हुए उम्मीदवार अपने-अपने राज्यों के विधायक या सांसद बन जाएंगे। तेलंगाना में 17 संसदीय सीटें होंगी जबकि सीमांध्र में 25 सीटें।

(साभार : जनसत्ता)